सुविचार

जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही सच्ची राह पर चलता है।

– प्रेमानंद महाराज

Daily THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

12

Alia Bhatt Wears a mask...

Ranchi ● Saturday, 07 December 2024 ● Year : 02 ● Issue : 314 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

SHARE

संसेक्स	:	81,765.86
निफ्टी	:	24,708.40

SARAFA

सोना	:	7,320
चांदी	:	101.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

बीएसएफ जवानों ने पकड़ा पाकिस्तानी ड्रोन व हेरोइन

CHANDIGADH : बीएसएफ ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत अमृतसर व तरनतारन में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में हेरोइन व पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते यहां घुसपैठ की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो रही है। कोहरे को देखते हुए पंजाब पुलिस व बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। बीएसएफ प्रवक्ता के अनुसार गुरुवार की देर रात चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान अमृतसर जिले के अंतर्गत पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके से 520 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसी तरह तरनतारन जिले में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 530 ग्राम हेरोइन तथा एक डीजेआई एआईआर थ्री एस ड्रोन बरामद किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हेरोइन की यह खेप ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में गिराई गई थी।

मिशेल को मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

NEW DELHI : चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को वर्ष 2024 के 'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' के लिए चुना गया है। कांग्रेस से संबद्ध संस्था 'इंदिरा गांधी स्मारक न्यास' ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी। पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विज्ञप्ति के अनुसार, मिशेल को शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और विकास में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 'इंदिरा गांधी स्मारक न्यास' द्वारा 'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' प्रति वर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है, जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विज्ञप्ति में कहा गया है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए आवाज उठाने को लेकर जानी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और चिली की राष्ट्रपति के रूप में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने देश और दुनिया भर में लैंगिक समानता एवं आबादी के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए दृढ़ता से आवाज उठाई है।

एक दिन के लिए किसानों का मार्च स्थगित

CHANDGADH : पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा दागे गए आंसूगैस के गोले के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया। पंधेर ने कहा, कुछ किसानों के घायल होने के मद्देनजर हमने आज के लिए जत्था वापस बुला लिया है। किसान नेता ने दावा किया कि हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण पांच से छह प्रदर्शनकारी किसान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के दो मंच संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा, एक बैठक के बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को दी विभागों की जिम्मेदारी

AGENCY RANCHI : शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी। गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभागों से संबंधित एक चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। इसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा कर दिया। गुरुवार 5 दिसंबर को 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के उपरांत हेमंत सोरेन कैबिनेट की टीम मुकम्मल हो गई थी। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्री है। इससे पहले पूरी कैबिनेट में 10 ही मंत्री थे। नव निर्वाचित मंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से छह, कांग्रेस से चार और राष्ट्रीय जनता दल से एक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों की शपथ के 26 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे विभागों का बंटवारा कर दिया। सीएम ने अपने पास, गृह, कार्मिक प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ पथ और भवन निर्माण विभाग अपने पास रखा है।

शपथ ग्रहण के बाद विभागों के बंटवारे का किया जा रहा था इंतजार

राधा कृष्ण किशोर को वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग का मिला दायित्व

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

विभाग
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, गृह (कारा सहित),पथ निर्माण, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित) तथा वैसे सारे विभाग, जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हैं।

राधाकृष्ण किशोर, मंत्री

विभाग
वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग।

दीपक बिरुआ, मंत्री

विभाग
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (निबंधन रहित), परिवहन विभाग।

चमरा लिंडा, मंत्री

विभाग
एसटी-एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) विभाग

संजय प्रसाद यादव, मंत्री

विभाग
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, उद्योग विभाग।

रामदास सोरेन, मंत्री

विभाग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निबंधन विभाग।

इरफान अंसारी, मंत्री

विभाग
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग।

हफीजुल हसन, मंत्री

विभाग
जल संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री

विभाग
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग।

योगेंद्र प्रसाद, मंत्री

विभाग
पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

सुदिव्य कुमार, मंत्री

विभाग
नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।

शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री

विभाग
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिया टास्क, लाभुकों से लें फीडबैक

AGENCY RANCHI : गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार होने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागीय कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परामर्श दिया। उन्होंने सभी मंत्रियों को इस कार्यकाल के लिए टास्क दिया है। इसके आधार पर वे अपने विभागों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मंत्री योजनाओं के विषय में लाभुकों के पास जाकर फीडबैक भी लेंगे। उन्होंने लंबित योजनाओं की समीक्षा करने के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान 17 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद में भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग से भी संपर्क करें, ताकि ससमय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सके। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें तथा विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक लें। विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करने के साथ सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का अध्ययन करें।

- जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यकलाप की करें समीक्षा
- विभागीय योजनाओं को समझ कर उनके गुण-दोष का करें अध्ययन

बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री ● फोटोन न्यूज

इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा

- वैसे विभाग, जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करें।
- भवन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली योजना की विशेष समीक्षा करें ताकि बने हुए भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अनावश्यक भवन आदि की योजना न ली जाए।
- वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करें।
- अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी की प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें।
- पदस्थापना की समीक्षा करें और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर एडजस्टमेंट करें।
- आप्त सचिव तथा निजी स्टाफ रखते समय उसकी पृष्ठभूमि जरूर देख लें, ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान न पाएं।
- कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें, ताकि सरकार केस कम से कम हारे।
- अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहां की समस्या के निपटारा के लिए प्रयास करें।
- क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के दौरान फीडबैक प्राप्त करें और मुख्यमंत्री को समय-समय पर अवगत कराएं।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण कर दें, ताकि सभी को सहूलियत हो।
- सभी मंत्री समय-समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे।

अष्टलक्ष्मी महोत्सव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तरमय हो गई दिल्ली

AGENCY NEW DELHI : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव को समर्पित डाक टिकट का भी विमोचन किया। पहली बार मनाया जा रहा तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 8 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत संविधान निमार्ता डॉ. भीमराम अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का बनाया संविधान और संविधान के 75 वर्ष के अनुभव देशवासियों के लिए प्रेरणा हैं। भारत मंडपम के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में यह स्थान जी-20 के सफल आयोजन सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविधता भरे रंग आज राजधानी में सुंदर इंद्रधनुष बना रहे हैं। यह तीन दिवसीय महोत्सव पूरे देश और विश्व को पूर्वोत्तर का सामर्थ्य दिखाएगा। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजूमदार आदि उपस्थित थे।

- भारत मंडपम में 8 नवंबर तक चलेगा यह तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन
- बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि
- पूर्वोत्तर के किसानों, कारगीरों और दुनिया के निवेशकों के लिए यह बेहतर अवसर

अनोखा आयोजन

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वोत्तर के किसानों, कारगीरों, शिल्पकारों के साथ-साथ दुनिया के निवेशकों के लिए भी बेहतर अवसर है। ये पहला और अनोखा आयोजन है, जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ-ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ-ईस्ट के किसानों, कारीगरों व शिल्पकारों के साथ-साथ दुनियाभर के निवेशकों के लिए भी बेहतरीन अवसर है। उन्होंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजकों को नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों के निवासियों और यहां आए सभी अतिथियों को बधाई दी।

लोस में नहीं हुआ कामकाज सोमवार तक के लिए स्थगित

AGENCY NEW DELHI : शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा। फिर दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थापित कर दिया गया। लोकसभा में सुबह विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। इसपर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से पूछा कि किया वे सदन को चलने नहीं देना चाहते।

● सोरोस मुद्दे और नोटों की गड्डी मिलने पर दोनों तरफ से देर तक होता रहा हंगामा

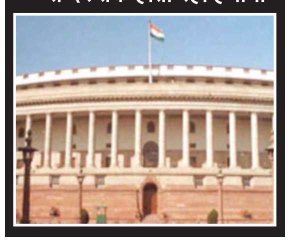

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा, आठ की मौत, 12 जख्मी

AGENCY LUCKNOW : शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली जा रही एक बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पौधों की सिंचाई करने वाले पानी के एक टैंकर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायलों को इलाज के लिए पास के इटावा जिले के सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा, यह दुर्घटना अपराह्न करीब दो बजे सकरावा इलाके में हुई, जब बस एक्सप्रेसवे पर पानी के टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में आठ यात्रियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायलों का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया। दुर्घटना के समय वहां से गुजर रहे जल शक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घायलों को बचाने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने के लिए अपना काफिला रुकवाया।

चिंताजनक भारत में 20% साइबर हमलों में किया गया नई तकनीक का प्रयोग

साइबर अपराध में तेजी से बढ़ रहा डार्क वेब का इस्तेमाल

AGENCY NEW DELHI : साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक से मानव जीवन को एक ओर सुविधाएं हासिल होती हैं, तो दूसरी ओर नई समस्याओं का जन्म भी होता है। आज के हाईटेक युग में हमारी तमाम जरूरतों की पूर्ति करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका सर्वोपरि हो गई है। दैनिक जीवन से लेकर अन्य तमाम पहलुओं को टेक्नोलॉजी नियंत्रित कर रही है। दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में भी नई-नई शैली अपराधियों द्वारा अख्तियार की जा रही है, जो भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक साइबर अपराध की नई-नई गतिविधियां साबित हो रही हैं। साइबर अपराध के क्षेत्र में डार्क वेब का इस्तेमाल सर्वाधिक डरावना साबित हो रहा है। हाल की एक स्पेशल रिपोर्ट से भारत में कम से कम 20 प्रतिशत साइबर अपराधों को अंजाम देने में ऑनलाइन हमलावरों द्वारा डार्क वेब के इस्तेमाल का खुलासा किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 'डार्क वेब' इंटरनेट पर एक ऐसा मंच है, जहां तक विशेष उपकरणों का उपयोग कर पहुंचा जा सकता है। डार्क वेब का इस्तेमाल करने वालों की पहचान और उनकी जगह का पता लगाना आमतौर पर बेहद मुश्किल होता है। साइबर सुरक्षा कंपनी लिसिएंथस टेक ने यह विशेष रिपोर्ट जारी की है।

विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए डार्क वेब तक पहुंचते हैं साइबर अपराधी

इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वालों की पहचान करना आमतौर पर मुश्किल

- साइबर सुरक्षा कंपनी लिसिएंथस टेक की स्पेशल स्टडी में सामने आई सच्चाई
- इस क्षेत्र के अनेक मामलों के विस्तृत विश्लेषण के बाद तैयार की गई रिपोर्ट
- मादक पदार्थों तथा हथियारों जैसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री व खरीद में भी उपयोग

क्या है डार्क वेब

डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है, जो सर्च इंजनों को दिखाई नहीं देता है। उस तक पहुंचने के लिए टोर नामक एक अनाम ब्राउजर का उपयोग करना पड़ता है। लंदन के किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डैनियल मूर और थॉमस रिड ने 2015 में पांच सप्ताह में 2,723 लाइव डार्क वेब साइटों की सामग्री को वर्गीकृत किया था।

हैकिंग, फिशिंग और डेटा सेंधमारी

इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत में कम से कम 20 प्रतिशत साइबर अपराधों में ऑनलाइन हमलावरों ने डार्क वेब का सहारा लिया। साइबर अपराधी आमतौर पर डेटा सेंधमारी, हैकिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, मादक पदार्थों तथा हथियारों जैसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री व खरीद जैसे साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए 'डार्क वेब' का इस्तेमाल करते हैं।

दिल्ली एम्स पर रैनसमवेयर हमला

पिछले साल दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर रैनसमवेयर हमलों के लिए भी हमलावरों ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया था। गुरुग्राम स्थित लिसिएंथस टेक साइबर सुरक्षा ऑडिट तथा सुरक्षा आकलन का काम करती है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में डार्क वेब का इस्तेमाल दोगुना हो गया है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि इसका शिकार होने से बचने के लिए उपयोगकर्ता को अपने फोन और अन्य उपकरणों पर ऐप तक पहुंच मांगने वाले किसी भी ऑनलाइन नोटिफिकेशन को इजाजत नहीं देनी चाहिए।

पानीपत की धागा फैक्ट्री में लगी आग दो मजदूर जिंदा जले

CHANDIGADH : पानीपत की धागा फैक्टरी में बीती रात लगी आग में पांच कर्मचारी झुलस गए। इनमें दो की मौत हो गई। तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों ने अंदर से इन पांच कर्मचारियों को निकाला। जानकारी के अनुसार, इसराना उपमंडल के अंतर्गत गांव बलाना में शिव फैब्रिक नाम की धागा फैक्ट्री में रात करीब साढ़े 12 बजे यहां आग लग गई। इसके बाद कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री के मालिक ने बताया है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इसके बाद फैक्ट्री में रात के समय मौजूद 2 कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। मृतकों की पहचान सुमित और तसमिल के रूप में हुई है। आग से बिल्डिंग और माल के साथ मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की सूचना मिलते ही सोनीपत, गोहाना व आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले

देश के लिए मुद्रास्फीति के 'घोड़े' पर लगाम लगाना बड़ी जरूरत

AGENCY MUMBAI : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत ब्याज दर को लगातार 11वीं बार अपरिवर्तित रखने पर शुक्रवार को कहा कि उनका प्रयास मुद्रास्फीति रूपी ह्यघोड़ेह्व को काबू में रखने पर केंद्रित है। दास ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुद्रास्फीति और वृद्धि के बीच संतुलन 'अस्थिर' हो गया है, लेकिन इसे दोबारा सही स्थिति में लाने के लिए सभी तरीके आजमाए जाएंगे। उनका इशारा दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि के उम्मीद से कहीं कम 5.4 प्रतिशत रहने और अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से अधिक रहने की तरफ था। आरबीआई गवर्नर के तौर पर अगले हफ्ते अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे दास ने यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की विश्वसनीयता भविष्य में भी बनी रहे।

● केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर को 11वीं बार रखा अपरिवर्तित

पंजाब से झारखंड आ रही अवैध शराब की बड़ी खेप गढ़वा में पकड़ी गई, तीन गिरफ्तार

कंटेनर में लादी गई थी 710 पेटी शराब, नगरउंटारी में चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर

मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी व थाने में जब्त शराब की पेटियां व बोतलें • फोटोन न्यूज

AGENCY PALAMU : पंजाब के लुधियाना से झारखंड आ रही अवैध शराब की बड़ी खेप गढवा जिले में पकड़ी गयी है। इस सिलसिले में हरियाणा के दो और राजस्थान के एक तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब लाखों की बतायी गयी है। एसपी दीपक पांडे ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लुधियाना से अवैध विदेशी शराब लदा कन्टेनर वाहन विण्डमगंज (उ.प्र.) की ओर से नगर उंटारी होते हुए बिहार एवं झारखण्ड के अन्य स्थानों पर जाने वाली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वंशीधरनगर के नेतृत्त्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। नगर उंटारी थाना गेट व नगर उंटारी थाना क्षेत्र के सिरिया टोंगर में अवैध शराब के परिवहन के विरोध चेकिंग लगाया गया। इस बीच एक कंटेनर वाहन सं.(यूपी-21-ईटी-0940) तेजी से आया, जिसे चेकिंग कर रहे पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल ने रोका और उसमें लोड सामान के बारे पूछा गया। चालक ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लोड होने की जानकारी दी। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। तब चेकिंग कर रहे पुलिस पदाधिकारी ने चालक से कंटेनर खोलकर दिखाने के लिए बोला गया। इस पर चालक ने अवैध विदेशी शराब लोड होने की बात कही। पुलिस और सेल्स टैक्स ऑफिसर से बचने के लिए अवैध विदेशी शराब लोड कंटेनर के आगे-आगे कार में दो व्यक्ति स्कोर्ट कर चल रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों को भी छापेमारी दल ने पकड़ा। इस संबंध में नगर उंटारी थाना कांड सं0-241/2024, दिनांक-05.12.2024 धारा-274, 275, 292, 338, 336 (3), 111/3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 47 (एं) उत्पाद अधिनियम दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गणपत लाल (35) पादरडीह, पो.-सिंदास्या थाना-गुडामलानी, जिला बाड़मेर (राजस्थान), पिंटु सैनी (39) म.न.- 262, 25, गली नं.-17 मनोहरनगर, बसीरोड, पटौदी चौक, थाना न्यु कॉलोनी गुड़गांव एवं इसी क्षेत्र के अमित कुमार (41) शामिल हैं।

कई ब्रांड की विदेशी शराब

कंटेनर वाहन से 710 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक्स सामान से संबंधित फर्जी दस्तावजे एक कार (एचआर 26 डीजेड 2900) आदि बरामद किया गया है। शराब में 425 पेटी में 5100 पीस 750 एमएल की मैकडॉवेल की बोतल, 190 पेटी में 9120 पीस 180 एमएल की मैकडॉवेल बोतल, 45 पेटी में 2160 पीस 180 एमएल व्हाइट ब्लू की बोतल, 50 पेटी में 1230 पीएस 500 एमएल की बुडवेइसेर मैग्नम की शराब बरामद हुई है।

घटनास्थल पर जुटे लोग • फोटोन न्यूज

लातेहार में कोयला व्यवसायी के घर पर की गई फायरिंग

LATEHAR : बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में स्थित कोयला व्यवसाय मुकेश कुमार सिंह के घर पर अपराधियों ने जमकर फायरिंग की। इस घटना से लोगों में डर का माहौल बन गया है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन अपराधी मुकेश सिंह के घर के पास पहुंचे इनमें से दो अपराधी मोटरसाइकिल से नीचे उतरे और मुकेश सिंह के दरवाजे के पास पहुंचकर फायरिंग आरंभ कर दिया। लगभग 6 से 7 राउंड तक फायरिंग करने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद डीएसपी विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा और उसके आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी आरंभ कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इधर घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन अपराधी आए थे और मुकेश सिंह के घर के पास लगभग 6 से 7 राउंड फायरिंग किया।

BRIEF NEWS

बाबा साहब का योगदान प्रेरणादायक : सकलदीप

KHUNTI : श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, मुरहू में शुक्रवार को भारतीय संविधान के निमार्ता डॉ भीमराव आंबेदकर की 69वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरूआत उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर संस्थान के निदेशक सकलदीप भगत ने कहा कि बाबा साहेब एक लोकप्रिय समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ तथा संविधान निमार्ता थे। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उनको समाज तथा स्कूल में छुआछूत का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद अपनी पढ़ाई के बल पर उनके पास 32 डिग्रियां थीं। साथ ही वे नौ भाषाओं के ज्ञाता थे। मरणोपरांत उन्हें भारतरत्न से भी सम्मानित किया गया। सभी छात्र-छात्राओं को उनके जीवन को आत्मसात करते हुए बेहतर शिक्षा ग्रहण कर देश का नाम रोशन करना चाहिए। शोषित और वंचितों के उत्थान में डॉ आंबेदकर का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस मौके पर शिक्षिका सावित्री और रिया के साथ सभी विद्यार्थी मौजूद थे।

मध्याह्न भोजन पर विशेष ध्यान की जरूरत: ज्योति

KHUNTI : उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर शुक्रवार को खूंटी प्रखंड के कुमकुमा गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ ने विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, स्वच्छता और योजना के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने रसोईघर, खाद्य भंडारण व्यवस्था और भोजन की साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने मध्याह्न भोजन से संबंधित उनकी राय जानी और योजना को और प्रभावी बनाने के सुझाव भी प्राप्त किए। बीडीओ ज्योति कुमारी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य न केवल बच्चों को पोषण प्रदान करना है, बल्कि उनकी नियमित उपस्थिति और शिक्षा में रुचि बढ़ाना भी है।

'बच्चों का भविष्य संवारना सबका कर्तव्य'

DHANBAD : डालसा द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि बच्चे देश के सुनहरे भविष्य हैं। उन्हें संवारना और सजाना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि नालसा के निर्देश पर बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली लीगल एड दिया जाएगा। यह यूनिट नालसा द्वारा प्रायोजित वात्सल्य तथा सहयोग योजना के तहत मिलने वाली हर सरकारी योजनाओं-सुविधाओं को भी बच्चों को दिलाने में सहयोग करेगा। सर्वोच्च न्यायालय (नालसा) के निर्देश पर धनबाद में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री लीगल सर्विस यूनिट का गठन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में गठित कमेटी का अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन को बनाया गया है।

सुरूंगा में मुआवजे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

DHANBAD : सुरूंगा गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा रैयती और अनाबाद जमीन पर डंपिंग करने और मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। इसकी शिकायत मिलने पर शुक्रवार को अंचल अधिकारी बलियापुर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बीसीसीएल के पदाधिकारी व ग्रामीण भी शामिल हुए। अंचल अधिकारी ने बीसीसीएल के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रैयतों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। रैयतों को उनके अधिकार हर हाल में दिए जाने चाहिए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना किसी मुआवजे या सहमति के उनकी जमीन पर जबरन डंपिंग की जा रही है। न किसी रैयत को मुआवजा दिया गया है, न ही भू अर्जन प्रक्रिया शुरू की गई है और न ही नौकरी की कोई बात हुई है। इस स्थिति से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।

लातेहार में खुलेगा राइस मिल प्रस्ताव बनाने का दिया निर्देश

समाहरणालय सभागार में बैठक करते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता • फोटोन न्यूज

LATEHAR : समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ के निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसमें संघ के अध्यक्ष सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता भी थे। उन्हीं की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सह संघ की सचिव जगमनी टोपनो ने बताया कि लातेहार में धान की खेती अधिक मात्रा में होती है, परंतु जिले में एक भी राइस मिल नहीं है। इस पर उपायुक्त ने संघ को राइस मिल का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिले में वनोत्पाद की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उपज के आधार पर प्रोसेसिंग यूनिट का अधिष्ठिपन किया जा सके। इससे पूर्व संघ कार्यालय का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए सुरेश कुमार वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी को लेखा पदाधिकारी के रूप नामित करने का निर्णय लिया गया एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सुदर्शन प्रसाद को नामित किया गया। संघ का जिला प्रतिनिधि सत्येंद्र कुमार यादव को गुप्त मतदान से निर्वाचित किया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अमृतेश सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा व जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रेयांश भी उपस्थित थे।

बोकारो में आभूषण दुकान में चोरी

BOKARO : शहर के सेक्टर 12-सी में गुनगुन जवेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपये के गहने पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार प्रमोद कुमार प्रसाद ने कहा कि वे दुकान बंद कर सोने चले गये थे। घटना की सूचना शुक्रवार की सुबह पड़ोसियों ने दी। जब देखा तो शटर के सभी ताले टूटे थे। लगभग तीस हजार के गहने की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि और गहने लॉकर में रखे थे, जो सुरक्षित है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। फॉरेनसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है तथा दुकान से फिंगर प्रिंट लेकर जांच शुरू कर दी है।

पलामू में टीएसपीसी का नक्सली गिरफ्तार आरोपी पर छह आपराधिक मामले हैं दर्ज

मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

AGENCY PALAMU : पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के दस्ता सदस्य 28 वर्षीय जितेन्द्र सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता जी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दस्ता को छोड़कर घर आने के कारण वह हथियार नहीं ला पाया था। जितेन्द्र जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैयाखुर्द का रहने वाला है। इसके खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले छतरपुर और नौडीहा बाजार थाना में दर्ज है।

एएसपी (अभियान) राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार दोपहर दो बजे एसपी कार्यालय के सभागार में बताया कि आज सुबह जिले की एसपी रीष्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य जितेन्द्र सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता जी नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बाराखाड़ डैम के पास आने वाला है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छतरपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई की गयी। बाराखाड़ पहुंचने पर देखा गया कि एक आदमी भौवराहा पहाड़ी की तरफ से चला आ रहा है। पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन जवानों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान हुई। उसने विभिन्न कांडों में अपना अपराध स्वीकार किया है। एएसपी ने बताया कि जितेन्द्र पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। छतरपुर में सबसे अधिक चार और नौडीहा बाजार थाने में दो मामले दर्ज हैं। 20 मई को सलैयाखुर्द में आपसी विवाद को लेकर ग्रामीणों की बेरहमी से पिटायी की थी।

युवक का अपहरण कर मांगी जा रही थी फिरौती, अपराधी हुआ गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी • फोटोन न्यूज

AGENCY RAMGARH : रामगढ़ शहर के एक युवक का अपहरण कर अपराधी फिरौती मांग रहे थे। लेकिन अपराधियों की योजना रामगढ़ पुलिस की सक्रियता से विफल हो गई। पुलिस ने ना सिर्फ अपहत युवक को सकुशल बरामद कर लिया बल्कि एक अपराधी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले की जानकारी शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि रामगढ़ शहर में फोटोग्राफी का काम करने वाले युवक अनिल कुमार का गुरुवार की शाम रामगढ़ बस स्टैंड से दो लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकताओं ने पहले तो अनिल के पास मौजूद सारी रकम लूट ली। इसके बाद उसी के मोबाइल फोन से उसके पिता को फोन कर 50 हजार रुपए की फिरौती की मांग की। इस मामले में एक अपराधी हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र निवासी अशफाक उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अपराधी लौहसिंघना थाना क्षेत्र के कल्लू चौक निवासी तौसीफ जावेद भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि पेशे से फोटोग्राफर अनिल बस स्टैंड में हजारीबाग की गाड़ी पकड़ने गया था। वहीं पर अशफाक और तौसीफ जावेद उसे मिले। उन लोगों ने अनिल को हजारीबाग तक लिफ्ट देने की बात कही। बाइक से वे लोग जब हजारीबाग की तरफ निकले तो रास्ते में ही उसके गले पर अपराधियों ने चाकू रख दिया। उसके सारे पैसे लूटने के बाद अनिल के पिता मुर्रामकला, ब्लॉक के पास रहने वाले दिनेश महतो को 50 हजार रुपए के लिए फोन किया। नहीं देने पर बेटे से हाथ धोने की धमकी दी। दिनेश महतो ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही एसपी अजय कुमार ने दो अलग-अलग टीम बनाई और अपराधियों को गिरफ्तार करने की योजना तैयार कर डाली। अशफाक और तौसीफ ने अपहरण की घटना को अंजाम देने के बाद फिरौती की रकम लेने के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया था। जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक उन लोगों ने अनिल को एक खराब पड़े बस में हाथ पैर बांधकर रखा था। एसपी ने बताया कि अपराधी लगातार अनिल के पिता को फोन लगा रहे थे और पैसे नहीं देने पर धमकियां दे रहे थे। अशफाक और तौसीफ अक्सर कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते थे।

घटनास्थल पर गिरे बाइक सवार • फोटोन न्यूज

दो बाइक की सीधी टक्कर में दो की मौत, तीन घायल

GUMLA : जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नवाडीह पंचायत अंतर्गत बिर्री पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की शाम दो बाइक के बीच सीधी टक्कर होने से बाइक सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों में बिर्री गांव निवासी अनमोल कुजूर (35) व पिंगल मिंज (30) शामिल हैं। घायलों में बिर्री निवासी जेम्स मिंज (45), प्रताप केरकेट्टा (30) व भेलवातला निवासी माइकल बरवा (32) शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को डुमरी साप्ताहिक बाजार था, जहां दोनों बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहे थे। इसी दौरान सीधी टक्कर हो गई। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार पांचों व्यक्ति सड़क पर गिर गए। दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों एवं राहगीरों के सहयोग से 108 नंबर डायल कर एंबुलेंस बुलाया गया और उससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया।

झारखंड व ओडिशा के बीच बिछेगी 228 किलोमीटर लंबी पटरी, 5603 करोड़ होंगे खर्च

राष्ट्रपति आज रखेंगी 3 रेल लाइनों की नींव

PHOTON NEWS JSR : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इन दिनों ओडिशा के प्रवास पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने रायरंगपुर स्थित आवास व गांव गईं। वे शनिवार को खड़गपुर मंडल के ओडिशा स्थित बांगरीपोसी स्टेशन से तीन नई रेल लाइनों का शिलान्यास करेंगी। इन परियोजनाओं में झारखंड और ओडिशा के बीच कुल 228 किमी लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे इस पर 5603 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इन लाइनों में चाकुलिया-बुड़ामारा, बादामपहाड़-क्योंझर और गोरुमहिषाणि-बांगरीपोसी रेल मार्ग शामिल हैं। चाकुलिया से बुड़ामारा के बीच 59.96 किमी लंबी रेल लाइन पर 1639 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मार्ग पर झारपोखरिया, न्यू जामशोला, बरोल, भादागोड़ा और लूलगापानी जैसे पांच स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा, 111 रोड ओवरब्रिज और कई छोटे-बड़े पुल बनाए जाएंगे। ओडिशा के बादामपहाड़ और क्योंझर के बीच 82.6 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण में 2106 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना में सात स्टेशन कलासबंध, टोंगाबिला, सिंघा, घोषदा, चेमना और खरतांगरी शामिल हैं। इसके अलावा, 131 रोड ओवरब्रिज और अन्य पुलों का भी निर्माण होगा।

राष्ट्रपति को जमशेदपुर आने का दिया निमंत्रण

JAMSHEDPUR : ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिशन (एआईएसडब्लूए) के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शुक्रवार को रायरंगपुर में मुलाकात की और 37वें अंतर्राष्ट्रीय संताली लेखक सम्मेलन के लिए जमशेदपुर आने का निमंत्रण दिया। 28-29 दिसंबर को जमशेदपुर के करनडीह में दिशोम जाहेर में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय संताली लेखक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव होगा। इस दौरान अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू, उपाध्यक्ष मदन मोहन सोरेन, महासचिव रवींद्रनाथ मुर्मू, सचिव अर्जुन मरांडी, चुनमन रघुन मुर्मू और हजाम बास्के भी उपस्थित थे। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपा, जिसमें संताली भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, नई दिल्ली में पंडित रघुनाथ मुर्मू व सुनाराम सोरेन भवन का निर्माण कराने, ओलचिकी लिपि के आविष्कारक पं. रघुनाथ मुर्मू को भारत रत्न देने, ओलचिकी लिपि का उपयोग करते हुए भारतीय मुद्रा में संताली भाषा को शामिल करने, रायरंगपुर में जनजातीय अनुसंधान केंद्र और डांडबुस हवाई अड्डे का नामकरण पं. रघुनाथ मुर्मू के नाम पर करने की मांग की गई। वहीं 37वें अंतर्राष्ट्रीय संताली लेखक सम्मेलन में भारत और विदेश से 600 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे।

रायरंगपुर स्थित राष्ट्रपति के आवास पर संथाली साहित्यकार • फोटोन न्यूज

सरायकेला में वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, तत्काल मौत

सड़क जाम करने वालों को समझाते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

SERAIKELA : सरायकेला थाना क्षेत्र के सरायकेला कांड्रा मार्ग पर शुक्रवार को नशे में धुत्त वाहन चालक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बांकसाई, सीनी ओपी के निवासी चंदन नापिल के रूप में हुई है। चंदन कोलाबिरा स्थित रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी में काम करता था। वह बाइक से ड्यूटी जा रहा था। यह घटना दुगनी कोलढीपी जियो पेट्रोल पंप के पास हुई। दुर्घटना के बाद, आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहन चालक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस किसी तरह उसे लोगों के चंगुल से बाहर निकालकर थाना ले गई। घटना के बाद, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों दिशा में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूली वाहन भी फंसे रहे। सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने और आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जैसे ही वह कोलढीपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रहे 407 वाहन ने उसकी बाइक को रौंद दिया।

Daily THE PHOTON NEWS सच के हक में...
www.thephotonnews.com
Saturday, 07 December 2024

वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हेमंत सरकार ने की तैयारी

टीकाकरण से मां और बच्चा दोनों रहेंगे स्वस्थ और सुरक्षित, यू-विन पर संरक्षित रखा जाएगा रिकॉर्ड

गर्भवती महिलाओं का समय पर किया जाएगा टीकाकरण, किसी भी सरकारी सेंटर पर लगवा सकते हैं टीका

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार ने महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ी योजना बनाई है। हम जानते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में से एक है, जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी के तहत झारखंड में भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की हेमंत सरकार ने व्यापक तैयारी की है, ताकि गर्भवती महिलाओं का समय से वैक्सीनेशन हो सके। इतना ही नहीं मां और बच्चों को

कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। यू-विन पर रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे देश में कहीं भी वैक्सीन लगवा सकते है।

कई बीमारियों के खिलाफ कारगर

एक्सपट्र्स की मानें तो समय से वैक्सीनेशन 11 बीमारियों के खिलाफ रोकथाम में कारगर है। इनमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन में होने वाली गंभीर टीबी, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के कारण होने वाली निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) शामिल हैं। जेई वैक्सीन केवल जिलों में लगाई जा रही है।

खुद से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सभी गर्भवती महिलाएं यू-विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर खुद पंजीकरण कर सकती हैं। यदि कोविन पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो यू-विन तक पहुंचने के लिए उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा, जिसमें महिला खुद को गर्भवती महिला के रूप में टैग कर सकती है और मौजूदा अभिभावक के खाते का उपयोग करके बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा निकटतम वैक्सीन सेंटर पर वॉक-इन/ऑन-साइट मोड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नवजात शिशु और बच्चे के माता-पिता के आधार नंबर के आधार पर आभा कार्ड बना सकते हैं। यू-विन पर

वैक्सीनेशन के लिए राज्य/जिला फिल्टर का उपयोग करके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर खोज सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग भी खुद के अनुसार कर सकते हैं। हर बार खुराक दिए जाने पर वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल रिसीविंग मिलेगी और डिजिटल ई-वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा।

मार्च 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों के 28,945 शिक्षकों को मिलेगा टैब

RANCHI : डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 28,945 शिक्षकों को मार्च तक टैब मिल जाएगा। टैब क्रय के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कंपनी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत टैब दिया जा रहा है। टैब के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी हो सकेगी। टैब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। एक टैब के क्रय पर लगभग 14 हजार रुपये खर्च आ रहा है। इसमें एक वर्ष तक टैब का मेंटेनेंस का खर्च भी शामिल है। टैब का स्क्रीन 10 इंच है।

BRIEF NEWS

पूजा सिंघल की याचिका पर अगली सुनवाई आज

RANCHI : नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दायर याचिका पर रांची के धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार को आशिंक सुनवाई हुई। सिंघल के अधिवक्ता की ओर बहस की गयी। इसके बाद ईडी की ओर से बहस की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है। इसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज

RANCHI : सरकारी टेंडर में कमीशन के जरिये करोड़ों रुपये की अवैध कमाई करने और उस कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की डिस्चार्ज याचिका खारिज हो गई है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया पर जेल में बंद निलंबित इंजीनियर वीरेन्द्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है। इन्हें ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ ईडी आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। इसपर कोर्ट संज्ञान भी ले चुका है।

हटिया डैम से शव मिला

RANCHI : शहर के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित हटिया डैम में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने हटिया डैम में शव को देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक, आसपास के लोगों से पहचान कराने पर युवक की शिनाख्त धुर्वा निवासी आतिश कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने इसके गुमशुदगी का मामला धुर्वा थाने में दर्ज कराया था।

गवर्नर व सीएम ने भीमराव अंबेडकर को किया नमन

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय संविधान के निमार्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर शुक्रवार को पोस्ट साझा किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत ने लिखा, ₹देश को संविधान रूपी ग्रंथ देने वाले महान नेता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शत-शत नमन। जय भीम।₹ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि-कोटि नमन।

नगर आयुक्त ने पदाधिकारियों व रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स के साथ की मीटिंग

पुराने भवनों को रेगुलराइज करने के सुझाव पर किया गया विचार

- राजधानी रांची के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर की व्यापक चर्चा
- मास्टर प्लान, लेआउट प्लान, पार्किंग, निर्माण कार्यों में विचलन पर भी विमर्श
- जिन बिंदुओं पर सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता तैयार किया जाएगा प्रस्ताव

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को नगर आयुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के पदाधिकारियों और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की बैठक हुईं। इसमें शहर के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। नगर आयुक्त ने शहर की आधारभूत संरचना के विकास और वर्तमान में आ रहीं कठिनाइयों पर विस्तृत परिचर्चा की। इस दौरान आर्किटेक्ट्स ने शहर के चौमुखी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव दिए। इनमें मास्टर प्लान, लेआउट प्लान, पार्किंग, निर्माण कार्यों में विचलन, पुराने भवनों का रेगुलराइजेशन, जर्जर भवनों का नवीनीकरण शामिल था। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि निगम स्तर पर जो कार्य निष्पादित होने हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की

जाएगी। जिन बिंदुओं पर राज्य सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता है, उन पर स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शहर में प्रदूषण कम करने, ग्रीन जोन बढ़ाने, ओपन स्पेस बढ़ाने और गली-मोहल्लों की व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में अपर प्रशासक फिलवियुस बारला, अपर प्रशासक संजय कुमार, नगर निवेशक राम बदन सिंह, नगर निवेशक शाखा के पदाधिकारी, झारखंड के सभी निबंधित आर्किटेक्ट व अन्य कर्मी उपस्थित थे। रांची नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की की अध्यक्षता में सभी जोनल सुपरवाइजर और वार्ड सुपरवाइजर के साथ बैठक हुई। इसमें गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग करते हुए स्त्रोत पृथककरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। बीट प्लान के अनुरूप कूड़े का उठाव और कार्यों के बेहतर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में नगर प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर और एमटीएस इंचार्ज मौजूद थे।

प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा सत्र को लेकर की बैठक, दिए निर्देश

PHOTON NEWS RANCHI : विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मराण्डी ने अपने कार्यालय कक्ष में षष्ठम्‌ विधान सभा के प्रथम सत्र को लेकर विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की। सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रोटेम स्पीकर ने राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नये सदस्यों के आवासन एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गए। मुख्य सचिव ने बैठक में स्पीकर को अवगत कराया कि सत्र को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। सत्र के दौरान पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था के अलावे आवश्यक जीवन रक्षक दवा और एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष ने दिये। साथ ही विधानसभा आने के क्रम में किसी भी प्रकार के अनावश्यक भीड़-भाड़ तथा उचित ट्रैफिक प्रबंधन के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि सत्र के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में वरीय पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किये जा चुके है। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता सहित संबंधित विभागों से सचिव और अन्य उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा।

रांची पुलिस ने बरामद किया दो करोड़ का गांजा

PHOTON NEWS RANCHI : शहर की ओरमांझी पुलिस ने दो करोड़ का गांजा बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 16 प्लास्टिक बोरा में लगभग 406.79 किलोग्राम गांजा, दो हजार नकदी, दो मोबाईल फोन और एक कंटेनर ट्रक (एनएल01 एन6915) बरामद किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में उत्तर प्रदेश निवासी धर्मवीर सिंह और धनबाद निवासी राजेन्द्र सिंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से रांची की ओर ट्रक से गांजा लोडकर ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एसएसपी ने बताया कि टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची-रामगढ़ मार्ग में उकरीद नकवाटोली के पास कंटेनर ट्रक को पकड़ा। तलाशी लेने पर ट्रक के केबिन के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे बने बॉक्स से कुल 16 प्लास्टिक के बोरों में 406.79 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गांजा को सम्बलपुर से लाकर टॉल गेट के आगे रामगढ़ में देना था। एसएसपी ने बताया कि बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये है।

राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला सैनिक कल्याण निदेशालय का शिष्टमंडल

RANCHI : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को सैनिक कल्याण निदेशालय का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर ह्यसशस्त्र सेना झंडा दिवसह्ण के उपलक्ष्य में बैज लगाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय सेना के सभी कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारे वीर जवानों के शौर्य, सतर्कता और समर्पण के कारण ही देश की सीमाएं एवं हम सभी देशवासी सुरक्षित हैं। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के जरिये युद्धकाल और आपदा के समय निभाए गए अतुलनीय कर्तव्यों और साहसिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा और बलिदान से हमारा राष्ट्र सदैव गौरवान्वित हुआ है। राज्यपाल ने राज्य के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपनी क्षमता के अनुसार 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' में योगदान देकर उन वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों के प्रति आभार प्रकट करें, जिन्होंने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, अनुपस्थित कर्मियों से मांगा स्पष्टीकरण

रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य समय से करें पूरा

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को रांची के प्रमंडलीय सभागार में आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागों के रेवेन्यू कलेक्शन पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुधार लाने के साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि वे विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करें। इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले रेवेन्यू वसूली में सुधार के लिए तेजी से कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस दौरान परिवहन, नीलाम पत्र, खनन, उत्पाद और मत्स्य विभागों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने जिला परिवहन अधिकारियों को वाहनों की जांच कर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही ओवरलोडिंग

वाहनों और छोटे वाहनों के परमिट की सघन जांच करने की बात कही। खनन विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने अवैध माइनिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध बालू उठाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं पकड़े गए अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी और एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए नीलाम पत्र अधिकारियों को तेजी से कार्य करने को कहा। बैठक में आयुक्त के सचिव आलोक कुमार, सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण हरिवंश पंडित, अवर सचिव नरेश गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद थे।

न्यायालय की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर भी विस्तार से की गई चर्चा

डीजीपी ने नक्सली विरोधी अभियान को लेकर की मीटिंग

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नक्सली विरोधी अभियान और न्यायालय की सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। बैठक में नक्सल के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक रूप से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में विगत दिनों में माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप, अपराधिक गुटों के जरिये राज्य के कुछ जिलों रांची, लातेहार, हजारीबाग, खूंटी एवं

चतरा में आगजनी, तोड़फोड़ की कुछ एक घटनाएं कारित की गयी है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिये गये। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा कि अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे एवं पूर्व में घटित घटनाओं में वैसे मामले जिनमें धमकी मिलने की पूर्व सूचना देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है, वैसे मामलों में संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी पुलिस अधीक्षक यह समीक्षा करेंगे कि माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप, अपराधिक गुटों के जरिये आगजनी-तोड़फोड़ से संबंधित मामलों में दर्ज किये गये काण्डों के अनुसंधान कर्ता कौन हैं? ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें काण्ड के अनुसंधान कर्ता थाना प्रभारी स्वयं हैं तथा कितने मामले में अन्य कनीय पदाधिकारी को अनुसंधान कर्ता बनाया गया है। इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सख्त निर्देश दिया गया कि माओवादी माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप, अपराधिक गुटों के जरिये किये गये आगजनी - तोड़फोड़ से संबंधित पूर्व में घटित सभी काण्डों का अनुसंधान थाना प्रभारी स्वयं ग्रहण करेंगे। सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित होने पर मामले का अनुसंधान थाना प्रभारी या पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को ही बनाया जाय। इसका अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

बाबा साहब अंबेडकर समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे : रविंद्र राय

PHOTON NEWS RANCHI : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र राय सहित अन्य नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर राय ने कहा कि भारतीय संविधान निमार्ता और भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर 69वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार

दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। दलितों के मसीहा अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, न्यायविद एवं अर्थशास्त्री भी थे। राय ने कहा कि भीमराव आंबेडकर की विरासत आज भी देशभर में प्रेरणा का स्त्रोत है। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के क्षेत्र में जो क्रांति शुरू की, वह हमेशा प्रासंगिक रहेगी. उनके विचार और योगदान वंचितों के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने कहा कि भारत में जब-जब संविधान और लोकतंत्र की बात होगी, बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर का नाम तब तब प्रमुखता से लिया जाएगा।

समाचार सार

विभिन्न संगठनों ने मनाई अंबेडकर की पुण्यतिथि

GHATSILA : संविधान निमार्ता बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि शुक्रवार को घाटशिला में विभिन्न संगठनों ने मनाई। अंबेडकरवादी अनुसूचित जाति कल्याण समिति के महासचिव संजय रजक की अध्यक्षता में बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। समिति के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सनत माझी, प्रणव माझी, आशीष माझी, मिहिर माझी आदि उपस्थित थे।

घाटशिला कॉलेज में हुआ अंबेडकर क्विज

घाटशिला कॉलेज में बाबा साहब की पुण्यतिथि प्रो. इंदल पासवान की अध्यक्षता में शुक्रवार को मनाई गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब के जीवन और योगदान विषय पर क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 12 समूह ने हिस्सा लिया। प्रत्येक समूह में 4 विद्यार्थी शामिल थे। सभी समूह के नाम पेड़ पर रखे गए थे। इससे पूर्व डॉ. दिलचंद राम, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संदीप चंद्रा, प्रो. अर्चना सुरीन आदि ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया।

उरांव समाज ने की वनभुजनी पूजा

CHAIBASA : शहर के बरकंदाज टोली व मेरी टोला में शुक्रवार को उरांव समाज ने वनभुजनी पूजा की। समाज के पनभरवा (पुजारी) फागु खलखो व उनके सहयोगी दुर्गा कुजूर, मंगरू टोप्पो, चमरू लकड़ा, संजय कुजूर, सुनील बरहा ने रात में पूजा-अर्चना कर मोहल्ले वासियों को हैजा, चेचक व मलेरिया जैसी मौसमी बीमारी से दूर रखने का आशीर्वाद मांगा। इस पूजा में मोहल्ले के सभी घरों के बाहर रात को आंगन में खाना बनाया गया। इसके बाद पूजा स्थल से ही छोटे-बड़े सभी बच्चे नंगे बदन हाथ में डंडा लिए मोहल्ले का भ्रमण किया। इस दौरान सभी घरों से एक-एक हंडी निकाल कर रखी थी, जिसे इन लड़कों ने डंडे से फोड़ा। हंडियों को फोड़ने के बाद सभी लड़के शमशान काली मंदिर में स्नान कर व वस्त्र पहनकर घर लौटे।

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए हुई कार्यशाला

CHAIBASA : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला जज मौहम्मद शाकिर और अन्य न्यायाधीशों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उद्घाटन अवसर पर शुक्रवार को मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में प्राधिकार के माध्यम से एलएसयूएम (मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए विधिक सेवाएं यूनिट) के सदस्यों के मध्य नालसा की दिव्यांग और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए योजना-2024 के अंतर्गत स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सभागार में शुरू किया गया। इस मौके पर शहर के जाने-माने चिकित्सक डॉ. सौम्या सेनगुप्ता भी उपस्थित थे।

सवारी गाड़ी के धक्के से 5 वर्षीय बच्चा घायल

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर प्रखंड के हिजिया गांव में छोटी सवारी गाड़ी ने एक 5 वर्षीय बच्चे को धक्का मार दिया, जिससे बच्चे का हाथ जख्मी हो गया। वाहन मालिक घायल बच्चे का इलाज करने से मुकर गया। पैसे के अभाव में घायल बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, चक्रधरपुर थाना अंतर्गत हिजिया गांव निवासी उदय अंगारिया का पांच वर्षीय बेटा पांडु अंगारिया घर के पास खेल रहा था। इसी क्रम में सवारी गाड़ी ने धक्का मार दिया और फरार हो गया। बच्चे के दायें हाथ में गंभीर चोट लगी है। इधर घटना की सूचना पाकर सामाजिक कार्यकर्ता सिंगराई जोंकों अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और परिजनों से कहा कि वाहन मालिक यथाशीघ्र बच्चे के इलाज में मदद नहीं करेगा, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाई फैशन की कहानी

JAMSHEDPUR : काशीडीह हाई स्कूल में शुक्रवार को जागृति नामक वार्षिक प्रदर्शनी लगी, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पहले स्टॉल पर प्राथमिक विंग द्वारा स्थानीय से वैश्विक तक भारतीय फैशन यात्रा की कहानी प्रस्तुत की गई। अन्य प्रदर्शनियों में भारत का साहित्य, भारत की खाद्य संस्कृति, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रही है, शामिल थे। अटल टिंकरिंग काउंटर पर छात्रों ने अपने नवाचारों और स्टार्टअप मॉडल का प्रदर्शन किया, जबकि अन्य काउंटर पर छात्रों ने दर्शाया कि कैसे भारतीय कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर उनके पोषण मूल्यों के लिए स्वस्थ विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

डिमना डैम के पास अपराधियों ने स्कूटी सवार को मारी गोली

पीछे से फायरिंग कर डिमना चौक की ओर भागे थे अपराधी, पुलिस कर रही जांच

PHOTON NEWS JSR: पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत डिमना डैम के पास शुक्रवार को देर शाम अपराधियों ने स्कूटी सवार आशुतोष ओझा उर्फ अंशु को गोली मार दी।

घटना के बाद आशुतोष के साथी मंगल ने उसे घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। आशुतोष को पीठ में गोली लगी, जो कंधे के पास से आर-पार हो गई।

डिमना डैम से लौटते वक्त हुआ हमला : मंगल ने बताया कि वह और आशुतोष डिमना डैम घूमने गए थे। लौटते समय आशुतोष स्कूटी के पीछे बैठा था। अलकतरा फैक्ट्री के पास घाटी में पीछे से गोली चलने की आवाज आई और देखा कि आशुतोष की पीठ से खून बहने लगा। फायरिंग करने वाले युवक डिमना चौक की ओर भाग निकले। इसके बाद आशुतोष को काली मंदिर मार्ग से अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस कर रही है जांच : घटना की सूचना मिलने पर साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा और डीएसपी मुख्यालय-1 भोला प्रसाद टीएमएच पहुंचे। उन्होंने घायल आशुतोष से पूछताछ की। हालांकि, पुलिस अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि गोली चली है या नहीं।

एमजीएम अस्पताल में घायल आशुतोष • फोटोन न्यूज

अमरनाथ हत्याकांड का गवाह है आशुतोष

घायल आशुतोष ओझा बासुकीनाथ में हुए अमरनाथ सिंह हत्याकांड का मुख्य गवाह है। उसी के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि यह हमला उसी केस से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन में घटिया ईंट लगाने का आरोप ग्रामीणों ने किया विरोध

GHATSILA : प्रखंड के आसना गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगा कर ग्रामीणों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों की सूचना पर जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने योजना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य के समक्ष जोरदार आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण में घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ईंट भरभराकर टूट रहा है। योजना से संबंधित बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि ग्रामीणों का विरोध जायज है। गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। मुर्मू ने कार्यस्थल पर मौजूद मुंशी को फटकार लगाते हुए घटिया ईंटों को हटाने का निर्देश दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि संवेदक ने कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंशी ने गलती स्वीकारते हुए जिला परिषद सदस्य और ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का भरोसा दिया। जानकारी हो कि आसना में 15वें वित्त आयोग की मद से जिला परिषद द्वारा भवन का निर्माण हो रहा है। इस मौके पर वार्ड सदस्य रामचंद्र मार्डी, किशुन टुडू, दारा सिंह मुर्मू, शीलू टुडू, बिक्रम टुडू, दुबई टुडू, संजय टुडू, गाजू टुडू, ठाकुर मुर्मू समेत अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।

आलू की आवक पर रोक से सीमा पर छिड़ा संग्राम, सड़क किया जाम

बंगाल से नहीं लाने दी सब्जियां, तो झुकी पड़ोसी राज्य की पुलिस

PHOTON NEWS GHATSILA : बंगाल से झारखंड में आलू के ट्रक नहीं आने दिया जा रहा है, जिससे आक्रोशित झारखंड के किसानों ने शुक्रवार को बंगाल के उन कारोबारियों-किसानों को रोक दिया, जो हरी सब्जियां ला रहे थे। गालूडीह थाना क्षेत्र में बंगाल सीमा पर शुक्रवार को बाघुडिया पंचायत के कई गांवों के किसानों ने झारखंड-बंगाल सीमा पर सड़क पर आवाजाही बंद कर दी। उन्होंने बंगाल से हरी सब्जी लाने वाले किसानों-व्यापारियों को रोक दिया। घटना की जानकारी के बाद बंगाल के बांदवान थाना प्रभारी मुमताज शेख एवं झारखंड के गालूडीह थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेने के बाद दोनों राज्य के किसानों को समझा कर मामले का समाधान किया। दोनों राज्य की सड़क पर लगभग 4 घंटा से लगा जाम हटाया। घटना के संबंध में किसानों ने बताया कि बुधवार को झारखंड के कुछ किसान आलू बीज लाने बंगाल के बांदवान गए थे। आलू बीज लाने के क्रम में बंगाल पुलिस ने सीमा पर रोक दिया। यही नहीं, पुलिस ने आलू के बीज भी जब्त कर लिए। इसके बाद किसान लौट आए। यहां बाघुडिया पंचायत के किसानों ने एकजुट होकर शुक्रवार को झारखंड बंगाल सीमा को जाम कर दिया। बंगाल पुलिस ने कहा कि जब तक आलू से बंगाल सरकार रोक नहीं हटा लेती, तब तक किसान अपनी बाइक पर आलू का बीज बंगाल से ला सकते हैं।

सड़क जाम करते ग्रामीणों को समझाते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

सड़क दुर्घटना में हुई वृद्ध की मौत

JAMSHEDPUR : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रिको सिग्नल के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना मे स्कूटी चालक गोलमुरी टुइलाडुंगरी निवासी 77 वर्षीय विश्वनाथ प्रसाद गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हे इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार दोपहर की है। शुक्रवार को विश्वनाथ के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस संबंध में विश्वनाथ के बेटे जयप्रकाश कौशल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

जयप्रकाश ने पुलिस को बताया कि पिता घर से सिदगोड़ा बाजार की ओर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन की तलाश कर रही है।

खड़े ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, स्कूटी सवार घायल

अस्पताल में इलाजरत घायल • फोटोन न्यूज

GHATSILA : धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के जयरामडीह-तामकपाल गांव के समीप शुक्रवार को स्कूटी सवार ने एनएच-18 पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी सवार अशोक दास गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने घायल को अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर रेफर कर दिया गया।

चिकित्सक ने बताया कि अशोक दास की आंख और सिर पर गंभीर चोट लगी है। घायल ने बताया कि वह जमशेदपुर से गोपीबल्लभपुर जा रहा था। पेट्रोल पंप के समीप अचानक आंख लग जाने के कारण ट्रक से टकरा गया।

'अपार आईडी' से सुरक्षित रहेगा लड़कियों का भविष्य

पटमदा में अभिभावकों के साथ बैठक करते पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार तृतीय अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, माचा (पटमदा) में मनाया गया, जिसमें छात्राओं के लिए 'यूनिफाइड ऑटोमैटिड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री' (अपार) आईडी बनवाने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके माध्यम से प्रत्येक छात्रा को सरकार द्वारा अपनी पहचान दी जा रही है। इससे आने वाली वार्षिक परीक्षा, माध्यमिक रजिस्ट्रेशन कक्षा 9 और 10 की जानकारी दी गई। कहा गया कि छात्राओं का जल्द से जल्द अपार आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें। शिक्षिका अलका कुमारी ने अभिभावक को बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर अभी परीक्षा की समय से तैयारी कराने का आग्रह किया। शिक्षिका पूनम कुमारी ने अभिभावकों का अभिनंदन किया।

बालू लदे 4 भारी वाहन जब्त, प्राथमिकी दर्ज

JAMSHEDPUR : उपायुक्त के निर्देश पर अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए जिला खनन कार्यालय द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बहरागोड़ा व बिरसानगर थाना क्षेत्र से बालू लदे 4 वाहन जब्त किए गए। चारों वाहन बिना खनिज परिवहन चालान के परिवहन करते हुए पाये गए। वाहनों को बहरागोड़ा एवं बिरसानगर थाना के सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

लोको पायलटों को 20-20 घंटे ट्रेन चलाने की धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल

डीआरएम का नाम लेकर चेतावनी देने का आरोप, मेंस कांग्रेस ने जताई आपत्ति

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोको पायलटों को 20-20 घंटे ट्रेन चलाने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर के एक चीफ लोको इंस्पेक्टर, जिसे सीएलआई कहा जाता है, द्वारा धमकी भरा ऑडियो जारी किया गया है।

खास बात यह भी है कि धमकी भी डीआरएम का नाम लेकर दिया जा रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद पूरे मंडल के रेल चालकों में आक्रोश है। हाल ही में रेल चालकों के शोषण और उन्हें 8 घंटे से ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए मजबूर करने का मुद्दा तूल पकड़ा था। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि लोको पायलटों का शोषण नहीं हो रहा है। उन्हें हर तरह की सुविधा देकर नियमानुसार तय समय सीमा तक ही ट्रेन चलवाया जा रहा है। इस ऑडियो को दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। मेंस कांग्रेस के महासचिव एसआर मिश्रा ने इस पर अधिकारियों से वार्ता कर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह धमकी देकर ट्रेन चालकों को 20-20 काम करने के लिए मजबूर करना बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेंस कांग्रेस के हस्तक्षेप से रेल चालकों के मन से कुछ हद तक भ्रम दूर हुआ है।

मुझे जानकारी नहीं है, पता कर रहा हूं : सीनियर डीसीएम

चक्रधरपुर रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक सह जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी ने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच की जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।

छात्रों ने कहा 50% सिलेबस भी नहीं हुआ पूरा, पहले बताया गया था विधानसभा चुनाव को कारण

को-ऑपरेटिव कॉलेज में डेढ़ महीने से इंटर की पढ़ाई बंद

PHOTON NEWS JSR : झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा इस बार 15 फरवरी के बाद शुरू होनी है। ऐसे में इस परीक्षा में ढाई महीने से भी कम का समय बचा है। इस समय पर जहां अधिकतर स्कूल व कॉलेज बच्चों का सिलेबस पूरा कराने में जुटे हैं। वहीं को-ऑपरेटिव कॉलेज में पिछले डेढ़ महीने से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद है, जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं। वे कॉलेज प्रशासन से कक्षाएं शुरू करने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन पहले चुनाव की वजह से कॉलेज के अधिग्रहण का हवाला देकर पढ़ाई बंद कर दी गई थी और अब इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने का हवाल देकर क्लास शुरू नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से कॉलेज में दाखिला लेने वाले 11वीं व 12वीं कक्षा के करीब 3 हजार छात्र परेशान हैं। छात्र लगातार इसे लेकर प्रिंसिपल व इंटर प्रभारी से मिल रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ उन्हें यह कहकर लौटा दिया जा रहा है कि कक्षा संचालन को लेकर जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। वहीं इस संबंध में जब कॉलेज के इंटर प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परीक्षा फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। इसलिए अभी कक्षाएं नहीं चल रही हैं।

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से बंद है पढ़ाई

इंटर के छात्र राहुल कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कॉलेज को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके बाद से ही इंटर की पढ़ाई को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। लेकिन 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद जब छात्र कक्षा संचालन की जानकारी लेने पहुंचे तो कहा गया कि क्लास रूम में प्रशासन की ओर से कुछ निर्माण कराया गया था। जब वह हट जाएगा, तब कक्षाएं शुरू होंगी। मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुए 15 दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है।

छात्रों ने कहा-बिना पढ़े कैसे देंगे परीक्षा

कॉलेज के इंटर के छात्र पंकज कुमार ने बताया कि जब इंटर की पढ़ाई कॉलेज में बंद हुई थी। उस समय हमारा सिलेबस 50 प्रतिशत पूरा हुआ था। इसके बाद कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। जबकि हमें उम्मीद थी कि चुनाव बाद जल्द कक्षाएं शुरू कर सिलेबस पूरा कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि बिना पढ़े हम परीक्षा कैसे देंगे। उनका कहना है कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। लेकिन सिलेबस अधूरा ही है।

> अभी बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जिसकी वजह से कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। जहां तक चुनाव के दौरान पढ़ाई बंद होने की बात है तो यह सही हैं। लेकिन इसके विकल्प में हमनें ऑनलाईन कक्षाएं संचालित कराया था। ऐसे में यह कहना कि पढ़ाई नहीं हो रही है यह गलत है।
>
> – डॉ भूषण कुमार, इंटरमीडिएट प्रभारी कोऑपरेटिव कॉलेज

एसबीआई ने लगाया नोट एक्सचेंज मेला

JAMSHEDPUR : मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा के ठोस प्रयास में, भारतीय स्टेट बैंक, बिष्टुपुर शाखा ने आरबीआई पटना के सहयोग से ग्रेजुएट कॉलेज, साकची में नोट और सिक्का विनिमय मेला का आयोजन किया। एक्सचेंज मेले का उद्घाटन शुक्रवार को आरबीआई के प्रबंधक श्रेय चौधरी और सहायक प्रबंधक मिथिलेश कुमार यादव ने किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि कटे-फटे और गंदे नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 रुपये मूल्य के सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं।

रेलवे यूनियनों की मान्यता के लिए मतदान हुआ संपन्न

चक्रधरपुर में मतदान के दौरान उपस्थित रेलकर्मी • फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : रेलवे यूनियनों की मान्यता के लिए बुधवार से शुरू हुई तीन दिवसीय मतदान प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। हालांकि अंतिम दिन सिर्फ रनिंग ब्रांच के कर्मचारियों ने ही मतदान किया। छह दिसंबर तक चलने वाली इस मतदान में चक्रधरपुर रेल मंडल के करीब 22 हजार रेलकर्मी मतदान करने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों ने मतदान किया। अन्य दो दिनों की तरह तीसरे दिन भी शाम छह बजे तक मतदान हुआ। इस चुनाव में मान्यता के लिए छह यूनियन जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसमें दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के बीच मुकाबला जोरदार देखने को मिला। राउरकेला और बंडामुंडा में आयोजित कुल आठ बूथों में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान आरपीएफ की पुख्ता सुरक्षा थी। अब 12 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित होगा। तब तक तमाम संगठनों के पदाधिकारियों-कर्मियों के धड़कने तेज रहेंगी।

परिवर्तित खेती

की आधुनिक युग में प्रासंगिकता

प्राचीन समय से अवधारणा है कि कृषि उत्पादन की तकनीक ऐसी होना चाहिए कि वह जीवन के पांच तत्व- भूमि, पानी, वायु, अग्नि एवं अंतरिक्ष (स्पेस) के प्रति सकारात्मक रहे। इस सर्वकालिक अवधारणा क अनुरुप, वर्ष 1980 के दशक से, परिवर्तित/जैविक खेती पर इस आधुनिकतम युग में सूक्ष्म अनुसंधान कार्य की निरंतरता बनाए रखी है इस अनुसंधान के महत्वपूर्ण बिन्दु जो उभर कर आये हैं वह इस प्रकार है।

भूमि जीवित है

मिट्टी में प्रचुर मात्रा में जैव कार्बन (0.5 प्रतिशत व अधिक) रहता है ऐसी भूमि में इन जीवों का वजन एक टन प्रति हेक्टेयर का अनुमान है। आबोहवा का कार्बन (सीओटू) हयूमस खेत के कचरे-बायोमास के विघटन से बनता है।

परिणामत

स्थानीय कचरा-बायोमास, खनिज, पशुओं का गोबर इत्यादि को जीवाणु कल्चर के संग आर्गेनिक मेन्यूअर-खाद के रुप में संवर्धित करें। संवर्धित मेन्यूअर उपलब्ध पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। उत्पादन-उत्पादकता, भूमि की जीवंत प्रणाली के इर्द-गिर्द घूमती है।

भूमि का संरक्षण

प्रकृति के अनमोल उपहार भूमि-मिट्टी, जीव एवं जीवाश्म व पानी-जल को खेत व खेत के आसपास संरक्षित और सजीवता की अहम भूमिका है। भूमि पर विषैले रसायन जैसे कीट, फफूंद व खरपतवार-चारा नाशक के उपयोग से परहेज करे। इन रसायनों के अधिक उपयोग से भूमि की सजीव प्रणाली शनैः - शनैः नष्ट हो जाती है। प्राण विहीन विषैली मिट्टी के रुखापन, सख्त-कठोरता से उत्पादन शक्ति कम होती है।

भूमि के जहर को निष्क्रिय करें

पौधे की बुनियाद-प्राण जड़ों में है। फिक्र जड़ों की करें, वह अपनी दृष्टि से दूर जमीन में रहती है। रुट झोन रायजोस्फीयर याने जड़ों के आस-पास में प्राण वायु का संचार, जल-नमी की उपलब्धता, भूमि का उचित तापमान, भूमि में जड़ो के विकास के लिए मुनासिब रहे यह बुनियादी आवश्यकता है। इस हेतु भूमि की गुडाई के साथ प्रोटीन हाइड्रोलायसेस का छिड़काव व भूमि पर पल्वार, तापमान को समायोजित रखते हैं। प्रोटीन हायड्रोलायसेट (गोबर, दाल या खली, गुड़, गोमूत्र, खमीर का किण्वन-फरमेन्टेशन प्रॉडक्ट) को भूमि की विषाक्ता-जहर को निष्क्रिय करने- जहर को उतारने हेतु भूमि व पौधों पर छिड़काव, अंकुरण के बाद में व 30-40 दिन की अवस्था में करें। यह छिड़काव पौधों की वृद्धि व भूमिगत जीवों की संख्या तेज गति से बढ़ती है। परिणामः ऐन टैगनिस्ट-शत्रु जीवाणुओं को समाप्त कर उपयोगी जीवाणु-माइक्रोफलोरा, पौध पोषण जो स्थायी अपरिवर्तनीय (फिक्सट) अवशोषणी (आयनिक) रुप में परिवर्तित होने पर पौधों की जड़ों में प्रवेश लेना संभव होता है।

कैसे- मोनोकाट फसलों में, जैसे गेहूं की जड़ों पर माईकोराइजा सहजीवी फफूंद पाई जाती है। इस फफूंद के हायपा सूक्ष्म दर्शी ट्यूब मोनोकाट की जड़ें व दलहन की जड़ ग्रंथियों के मध्य पोषक तत्वों की आवक-जावक में सहयोग करती है। यह त्रिपक्षीय सहयोग का उदाहरण है। इस प्राकृतिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए मोनोकाट गेहूं का पोषण हेतु रासायनिक/जैव खाद से प्राप्त होने वाले नत्रजन पर निर्भरता 70-80 प्रतिशत तक कम करना संभव होता है। इस प्राकृतिक सिद्धांत का लाभ लेना चाहिए। इसे किस प्रकार से निश्चित कार्य रुप दिया जाए? गेहूं के साथ में दलहनी चारा बरसीम/सेंजी (मिलीलोटस), लुसर्न को सहयोगी फसल के रुप में लगायें।

जल संवर्धन

प्राकृतिक संपदा मिट्टी, जीवाश्म व जल संवर्धन एक दूसरे के अनुकूल व संपूरक है। इस प्रकल्प की पूर्ति हेतु प्रत्येक खेत के आसपास मेढ़ के स्थान पर नालियां बनाए। प्रत्येक फार्म, फार्म के निकट पोखर/छोटी कुइया बनें। यह रिचार्ज-जल रिसन में सहायक होते है। तकनीक देखने में छोटी प्रतीत होती है पर परिणाम बहुआयामी है। भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। भूमिगत जल स्तर को तेजी से ऊपर उठानें हेतु, टयुब वेल-नलकूप क आस पास गहरे रिचार्ज सेफट बनाए। इसे पोखर-तालाब में भी बनाएं। ऊपरी पर्तो-प्रोफाइल के जल की गुणवत्ता बेहतर रहती है जो उर्वरा भूमि व कम्पोस्ट के संग उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना संभव हो जाता है विशेष कर मानसून आधारित खेती से भी। परिवर्तित खेती अपनाने पर खेती लाभ का व्यवसाय के साथ में सहायक रोजगार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लक्ष्य की पूर्ति संभव है। परिवर्तित खेती अपनाने पर रोजगार के अवसर में वृद्धि से युवा वर्ग भी ग्रामीण क्षेत्र के इकोफ्रेन्डली वातावरण में रहना पसंद करेगा।

उपसंहार

प्रस्तावित परिवर्तित खेती तकनीक के पक्ष में ठोस वैज्ञानिक अनुसंधन के सकारात्मक निष्कर्ष है। इस विषय पर वृद्ध विवेचना पुस्तक परिवर्तित खेती व पर्यावरण सुरक्षा लेखक वि-न.श्रॉफ में दी गई है। यह मौलिक ग्रंथ है, जो दक्षता के साथ तर्क-वितर्क के चातुर्य से आश्वस्त करते हुए अपील की गई है कि पुनः परिवर्तित-जैविक खेती को अपनाया जाय। इस पुस्तक को कृषि कार्यमाला का व्यवहारिक रुप दिया गया है। इस में प्रत्येक स्टेक होल्डर को लक्ष्य में रखा है, जैसे कृषक, उपभोक्ता, अनुसंधानकर्ता, विद्यार्थी, ट्रेनर-प्रशिक्षक, व्यवसायी, सामाजिक नियोजनकर्ता इत्यादि को। द्वितीय हरितक्रांति की सफलता का आधार स्तंभ है, ज्ञान व दक्षता। सदाबहार उच्च उत्पादन को प्राप्त करने का लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हुए। इस के साथ में हरित-ग्रीन जी.डी.पी. विकास जौ विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थो की कीमतों की उथल-पुथल को नियंत्रण में रखते हुए। मंदी के दौर से उभरते हुए, भूख व कुपोषण से निजात पाने में प्रस्तावित तकनीक सहायक है। इस से ही सामाजिक न्याय की परिकल्पना को मूर्त रुप देने में सफलता मिलेगी।

जैव विविधता

प्रत्येक फार्म के चारों तरफ कई प्रकार की वनस्पति होना चाहिए। पौधे जिसका उपयोग कीट नियंत्रण हेतु जैसे नीम, महुआ, रत्नजोत, गेंदा, तुलसी, सुर्जना, आयपोमिया, अकुआ, धतूरा, लहसुन, मिर्च, सीताफल की पत्तियां-बीज इत्यादि को स्थान दें। इस के उपरांत पक्षी, मेंढक, उल्लू, सर्प वर्ग के जीव, मित्र कीट को संरक्षण दे। यह प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखना में उपयोगी है। समस्त जीवों के हित में इसे संरक्षण दें फार्म के आस-पास ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अलावा प्राकृतिक आवास स्थलों में।

जैव उर्वरक के गुण

जैव उर्वरक (खेती के लिए एक अनिवार्य आदान-प्रदान)

पोषण भोजन सजीवों की प्राथमिक आवश्यकता है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है, जिसमें सभी तत्वों का आवश्यक एवं संतुलित मात्रा में होना अति आवश्यक है, पौधों के लिए मुख्यतः हवा, पानी, भूमि तथा उर्वरकों से प्राप्त होते है। पोषक तत्वों को पौधों की प्रायः अवस्था में बदलने का कार्य सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव ही जैव उर्वरकों के नाम से जाने जाते हैं, जो भोजन की पूर्ति के साथ-साथ फसल को कई प्रकार से लाभांवित करते हैं, जैसे पादप क्रियाओं में वृद्धि पौधों के लिए विटामिंस तथा हारमोन्स का निर्माण तथा उनका क्रियांवयन, एंटीबायोटिक व रोग निरोधक क्षमता का निर्माण तथा पौधों के जड़ भाग में नमी का संरक्षण कर अन्य कई प्रकार से पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हुए मिट्टी की उर्वरता को लम्बे समय उपजाऊ बनाने में सहायक है। अतः जैव उर्वरक भूमि की लम्बी आयु के द्योतक है।

राइजोबियम

यह जीवाणु सभी दलहन फसलों के जड़ भाग में ग्रंथि का निर्माण कर दलहन फसलों की 80-90 प्रतिशत मांग की पूर्ति करता है। जिसे बीजोपचार द्वारा 10 से 12 किलो बीज में एक राइजोबियम 200 ग्राम के पैकेट को एक गिलास पानी या चावल के माड में लेही बनाकर बीजों में मिलाया जाता है। तथा सभी दलहनों के लिए अलग-अलग विशेष राइजोबियम कल्चर का प्रयोग होता है।

एजेटोबेक्टर

यह जीवाणु कल्चर सभी फसलों के लिए नत्रजन की 15 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर तक की पूर्ति करता है।

एजोस्पिरिलिम

यह जीवाणु एजोटोबेक्टर जैसा ही जैव उर्वरक है तथा इसे बीजोपचार पौध-जड़ोपचार तथा मिट्टी उपचार द्वारा सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। तथा नत्रजन की स्थिरीकरण क्षमता 20-20 किलो प्रति फसल है।

एसीटोबेक्टर

यह जैव उर्वरक मुख्यतः गन्ने के लिए विशेष उपयोगी है। गन्ने के साथ-साथ शर्करा वाली फसलों के सम्पूर्ण भाग में पनपकर 65 से 150 किलो प्रति हेक्टर तक नत्रजन की पूर्ति करता है।

पीएसबी कल्चर

इसमें प्रयोग होने वाले जीवाणु खेत में पड़े फास्फोरस को जो कि पौधों को पूरी तरह प्राप्त नहीं होता, को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर फसल के लिए उपयोगी बनाता है जिससे व्यर्थ फास्फोरस का अधिकतम उपयोग हो जाता है जिससे फसल को 10-40 किलो फास्फोरस उपलब्ध होकर फसल में 7-21 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है तथा सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है।

वैम माइकोराइजा

यह जीवित लाभदायक फफूंदी जो फसलों के सम्पूर्ण जड़ भाग में पनपकर पौधों में फास्फोरस के साथ-साथ अनेक सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं तथा नमी संरक्षण व कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसका उपयोग बीजोपचार व पौध-जड़ोपचार द्वारा किया जा सकता है।

एजोला एवं बीजीए

एजोला एक जलीय खरपतवार है। इसे तालाब व झील आदि से एकत्रित कर धान के खेत में डाल सकते हैं। जबकि बीजीए कल्चर (5 किलो प्रति एकड़) को जैव उर्वरक उत्पादन केन्द्र से खरीद कर धान के खेत में रोपाई के समय प्रयोग करते हैं तथा दोनों ही अलग-अलग 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर नत्रजन की पूर्ति करते है। एजोला एवं बीजीए दोनों ही धान के लिये उपयोगी है।

कम्पोस्ट डिकम्पोजर

यह कल्चर गोबर की खाद व कम्पोस्ट की विच्छेदन क्रिया को तेल कर कम समय में खाद तैयार हो जाती

है तथा इस कल्चर को 1 से 3 प्रतिशत कच्चे खाद की मात्रा के अनुसार गड्ढों में मिला देते हैं।

रोग बायोकन्ट्रोलर

ऐसे बहुत से कल्चर अब बाजार में उपलब्ध होने लगे है कि जैविक क्रिया के उत्पादों द्वारा कई बीमारियों एवं कीट-लार्वा आदि से फसल सुरक्षा करते है तथा फसलों में कल्चर की तरह से प्रयोग किये जाते हैं।

प्लांट राजोबैक्टिरिया

इसमें प्राप्त लाभदायक सभी जीवाणु जो पौधों के जड़ क्षेत्र में पनपते हुए फसलों को विभिन्न प्रकार से लाभांवित करते हैं जिसमें मृदा, पौधों दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि

बीजोपचार

सीधी बिजाई वाली सभी फसलों के लिए बीजोपचार उत्तम तरीका है। इसके लिए नत्रजन देने वाले तथा फास्फोरस देने वाले एक-एक पैकेट को घोले पानी अथवा ठंडे चावल के मांड में लेही बनाकर 10-12 किलो बीज पर काली परत चढ़ाने तक मिलायें तथा छाया में सुखाकर तुरंत बिजाई करें।

पौध जड़ोपचार

रोपाई की जाने वाली सभी फसलों के लिए 2 किलो एजेटोबेक्टर/एजोस्पिरिलम तथा उतनी ही मात्रा में फास्फोटिका आवश्यक जल में घोल बनाकर एक-दो घंटे रखें तथा धान के लिए रात भर रखें। इससे एक एकड़ पौध की रोपाई की जा सकती है।

मिट्टी उपचार

चार किलो एजेटोबेक्टर एजोस्पिरलिम अथवा दोनों दो-दो किलो तथा चार किलो पीएसबी कल्चर को उचित नमी वाले 100 से 150 किलो गोबर की तैयार खाद में मिश्रण तैयार कर 24 घंटे बाद फसलों की जड़ वाले भाग में प्रयोग करें।

गहरी जुताई

बड़ी कमाई

रबी की फसल कटाई के बाद अप्रैल से जून तक मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क प्लाऊ से की जाने वाली जुताई ग्रीष्मकालीन जुताई कहलाती है। यह जुताई आगामी खरीफ फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है । एक ही प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे देशी हल या ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर आदि द्वारा खेतों की लगातार जुताई करते रहने के कारण भूमि में एक निश्चित गहराई में कठोर परत बन जाती है। इस आंतरिक कठोर सतह के कारण वर्षा का जल भूमि में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता। भूमि, वर्षा जल का नहीं हो पाने से जल बहकर खेत से बाहर निकल जाता है । जिससे भूमि में नमी का उचित संरक्षण नहीं हो पाता । इसको उपयुक्त दशा में लाने के लिए रबी की फसल काटते ही जुताई आंरभ कर देनी चाहिए। क्योंकि फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी में थोड़ी बची नमी में भी जुताई करने में आसानी रहती है । बाद में मिट्टी की नमी के वाष्पीकरण से खेत सूख जाते हैं और गहरी जुताई करना कठिन हो जाता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष खेतों की गहरी जुताई 40 सेमी. या इससे अधिक गहराई तक आवश्यक रूप से करनी चाहिए।

ग्रीष्मकालीन जुताई के निम्न लाभ हैं -

मिट्टी के जल सोखने की क्षमता में वृद्धि - खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी पलट जाती है और भूमि के अन्दर निर्मित कठोर सतह के टूट जाने से गहराई तक भुरभुरी बन जाती है । इससे मानसून की पहली वर्षा का अधिकांश पानी जमीन के अंदर चला जाता है जो खरीफ फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पहली वर्षा के जल में वायुमण्डल में उपस्थित नाइट्रोजन भी घुली होती है और यह जल भूमि में प्रवेश कर खेत की उर्वराशक्ति में बढ़ोतरी करती है । जमीन में वर्षा का पानी प्रवेश करने से भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है। वर्षा आधारित असिंचित कृषि में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का भी विषेश महत्व है क्योंकि ऐसी स्थिति में फसलों सें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्षा जल का अधिक मात्रा में भूमि के अंदर संचय होना आवश्यक है ।

मिट्टी के वायु संचार में वृद्धि - मिट्टी में बीजों का अंकुरण जड़ो की वृद्धि, उचित वायु संचार तथा मिट्टी जल को उचित मात्रा में बनाये रखने के लिए खेत में जैव कार्बनिक पदार्थ मिलाकर अच्छी प्रकार से जुताई करना चाहिए । जुताई से भूमि में जीवांश पदार्थ सड़कर पौध पोषक तत्वों में बदल मात्रा में बने रहते है तथा सूक्ष्म जीवों को उचित मात्रा में आक्सीजन मिलती रहती है ।

मिट्टी में उचित तापमान बनाये रखना- बोई गई फसल बीजों का अंकुरण कृषि भूमि के उचित तापमान पर निर्भर करता है । ग्रष्मिकालीन गहरी जुताई से मिट्टी अच्छी तरह पलट जाती है तथा भूमि के अंदर मिट्टी संरचना में सुधार होने से सूर्य की किरणें सीधी भूमि के अंदर पहुंच जाती है। इससे खरीफ फसलों के बोये गये बीजों का अंकुरण सही तापमान पर आसानी से हो जाता है तथा पौधों का विकस अच्छा होता हैं।

मिट्टी के गुणों में सुधार- भूमि की ऊपरी सतह पर रबी फसलों के बचे हुए पौध व खरपतवारों के अवशेश गर्मी में खेत की गहरी जुताई करने पर मिट्टी में अच्छी तरह से दब जाते हैं।

संघ प्रमुख का बयान: क्या वाकई अच्छे हैं तीन बच्चे

प्रो. लल्लन प्रसाद

भागवत जी का मानना है कि आबादी दर में गिरावट परिवार व्यवस्था के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। नई पीढ़ी में कम से कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहां तक कि कुछ नौजवान, नवयुवतियां एक बच्चा भी नहीं चाहते। यदि यही क्रम चलता रहा तो हिन्दू आबादी की विकास दर में कमी और मुस्लिम एवं क्रिश्चियन आबादी की विकास दर में वृद्धि हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना देगी। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉ मोहन भागवत का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने तीन बच्चे समाज के लिए अच्छे की बात कही है, बहस का भारी मुद्दा बन गया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने भी इस तरह का प्रस्ताव किया था। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, दुनिया की 2.4प्र. भूमि पर 17.5प्र. आबादी रहती है।

देश जब आजाद हुआ था तब कुल आबादी 36 करोड़ थी। अब 144 करोड़ है। इतनी तेजी से आबादी में जो वृद्धि हुई उसने भारत को चीन से भी आगे कर दिया है। प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जो अब 75 वर्षों के बाद पहले से और कम हो चुके हैं। यद्यपि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है, रोजगार के अवसर भी पहले से अधिक हैं किंतु आबादी चार गुना हो चुकी है। इसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की आबादी विकास दर 4प्र. कम हुयी है, जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 14प्र. बढ़ी है । कुल आबादी बढ़ी है किंतु प्रजनन दर में गिरावट आई है जो 2.1प्र. से भी नीचे जा चुकी है, जिसे आबादी की निरंतरता के लिए सुरक्षित सीमा कहा जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र भी बन गया है। देश के कई जिले, जो तीन-चार दशकों पहले ही हिन्दू बहुल थे विशेषकर उत्तर पूर्व के, अब मुस्लिम बहुल हो गए हैं।

आबादी में इतनी तेजी से वृद्धि किंतु प्रजनन दर में कमी, और उसके फलस्वरूप जनसांख्यिकी में परिवर्तन और सामाजिक तनाव आबादी पर बहस को हवा दे रहे हैं। भागवत जी का मानना है कि आबादी दर में गिरावट परिवार व्यवस्था के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। नई पीढ़ी में कम से कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहां तक कि कुछ नौजवान, नवयुवतियां एक बच्चा भी नहीं चाहते। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2021 में एक महिला जीवनकाल में 2.2 बच्चे जनती थी जो 2015-16 में 2 पर आ गई, अब और नीचे जाने की आशंका जताई जा रही है। 1950 मे यह 6.2 थी, 2021 में 2 हो गई और यदि यही क्रम चलता रहा तो 2050 में यह 1.29 और 2100 में 1.04 पर पहुंच जाएगी।

हिन्दू आबादी की विकास दर में कमी और मुस्लिम एवं क्रिश्चियन आबादी की विकास दर में वृद्धि हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना देगी। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है।

संघ ने 2015 में विशद आबादी नीति का प्रस्ताव किया था, 3 वर्षों बाद आबादी के लिए एक समान कानून की मांग सभी धर्मों के लिए की थी। समान आबादी नीति के लिए यदि मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबी भी राजी हो जाएं तो आबादी में असंतुलन और उसके विनाशकारी प्रभाव की स्थिति से बचा जा सकता है। 'हम दो हमारे दो' के बाद 'हमारे तीन' की बात विरोधाभास की स्थिति बना रही है। अधिकांश देश, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, गरीबी से जूझ रहे हैं, या विकास के पैमाने पर अभी भी विकसित पश्चिमी देशों से कहीं बहुत पीछे हैं। सबसे तेज आबादी का विकास सब-सहारन अफ्रीकी देशों में है, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

दक्षिण अमेरिका और भारत सहित दक्षिण एशिया के अधिकांश देश विकासशील की श्रेणी में आते हैं, जहां जीवन स्तर विकसित देशों की तुलना में नीचे है। भारत विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन चुका है, और अगले कुछ वर्षों में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाने की संभावना है, किंतु प्रति व्यक्ति आमदनी की दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 70000 डॉलर है जबकि भारत में मात्र 2700 डॉलर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 193 देशों में 134वें स्थान पर है जो सोचनीय है। स्विट्जरलैंड़ नंबर वन पर है, चीन 75वें स्थान पर है। यह सूचकांक तीन बातों का संज्ञान लेता है: लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर। भारत में जीवन प्रत्याशा विगत कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, इस समय यह 68 वर्ष है किंतु विकसित देशों में इससे कहीं अधिक है, जापान में 84 वर्ष और अमेरिका में 77 वर्ष।

शिक्षा से अभी भी करोड़ों बच्चे वंचित हैं, बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, बाल मृत्यु दर भी भारत में विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, मकान किराया, बिजली, पानी, यातायात आदि के बढ़ते खर्चों से आम आदमी त्रस्त है। देश में आर्थिक असमानता भी बढ़ी है, कुछ औद्योगिक घरानों और बड़ी कंपनियों के हाथों में देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा संचित है। आर्थिक विकास के साथ आम आदमी की आमदनी में वृद्धि हुई है किंतु उतनी नहीं जो इतनी बड़ी आबादी को खुशहाली दे सके। ऐसे में आबादी बढ़ाने की बात जब की जाती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। किंतु आबादी दर में गिरावट चिंता का विषय तो है। सामाजिक असंतुलन और तनाव के अतिरिक्त इसका एक दुष्प्रभाव और भी है-बच्चों और युवकों की आबादी में गिरावट और बूढ़ों की आबादी में वृद्धि जो स्थिति अधिकांश विकसित देशों में देखी जा रही है। यूरोप की आबादी आज लगभग उतनी ही है, जो दूसरे विश्व युद्ध के पहले थी। जन्म दर में भारी गिरावट के कारण आबादी नहीं के बराबर बढ़ी है। यूरोपीय देशों में श्रम की कमी के कारण शरणार्थियों को बसाने की होड़ लगी किंतु उसका घातक परिणाम उन्हें अब भोगना पड़ रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में तो यह संकट की स्थिति पैदा कर चुकी है, वहां सरकारें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं, करों में छूट दी जा रही है, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के लालन-पालन का खर्च, गर्भवती महिलाओं के लिए सवेतन छुट्टी आदि सुविधा दी जा रही है। मोहन भागवत का बयान पूरे भारतीय समाज के लिए है, सभी संप्रदाय के लोगों को मिल कर और नेताओ को सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश हित में समस्या का हल निकालने चाहिए। (लेख में विचार निजी हैं)

संपादकीय

फड़णवीस से उम्मीदें

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के करीब दस दिनों बाद तक यहां की राजनीति सस्पेंस फिल्म की तरह चलती रही और अंततः भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़णवीस के नाम की घोषणा के साथ इसका अंत एक थ्रिलर की तरह हुआ। फड़णवीस ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वस्तुतः भारत में गठबंधन की राजनीति जितनी आम हो गई है, उतनी जटिल भी। नैतिक मान्यता की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े. दल के रूप में उभर कर आई थी और इस नाते भाजपा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए था। लेकिन एकनाथशिंदे की पर्दे के पीछे की भूमिका के कारण फड़णवीस को प्रतीक्षा करनी पड़ी। फड़णवीस की राजनीतिक यात्रा की शुरूआत 1997 में नागपुर नगर निगम के महापौर के रूप में हुई। तब वह मात्र 27 वर्ष के थे। दो वर्ष बाद 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बन गए और 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनकी पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में है। पार्टी के भीतर उनका बहुत तेजी से उभार हुआ लेकिन इसके कारण भाजपा के अंदर कलह भी हुई। महाराष्ट्र जैसे बड़े. और महत्तवपूर्ण राज्य का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें भाजपा के भविष्य का चेहरा भी बताया जा रहा है। देशके अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र की भी अनेक समस्याएं हैं, जिनका फड़णवीस की सरकार को सामना करना पड़ेगा। आर्थिक-सामाजिक विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और वहीं पर बॉलीवुड़ है। देश के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां आते रहते हैं। लेकिन यह प्रदेश क्षेत्रीय असंतुलन का भी शिकार है जिसके कारण राज्य में कृषि क्षेत्रको काफी नुकसान उठाना पड़. रहा है। विदर्भ और अमरावती संभाग काफी पिछड़ा हुआ है जहां फसल का उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान सबसे अधिक आत्महत्या करते हैं। बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। फड़णवीस को इन चुनौतियों का सामना करते हुए गठबंधन के सहयोगी दलों को भी साथलेकर चलना होगा। वह विनम्र और प्रबंधकीय गुणों में निपुण हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की नई कहानी लिखेगा।

चिंतन-मनन

मन का क्रिय

एक प्रोफेसर अपने कमरे में बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आकर बोला, धन्यवाद, आप जैसा परिश्रमी और योग्य प्रोफेसर मैंने नहीं देखा। आपके परिश्रम से ही मेरा लड़का उत्तीर्ण हो सका है। सौ-सौ साधुवाद! इतने में दूसरा व्यक्ति आकर बोला, आप जैसा परिश्रम से जी चुराने वाला प्रोफेसर मैंने कहीं नहीं देखा। आपके कारण ही मेरा लड़का अनुत्तीर्ण हुआ। पहले व्यक्ति की बात सुनकर प्रोफेसर प्रसन्नता से झूम उठा और दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर वह विषण्ण हो गया। यह सारा खेल मन का है। एक घटना मन के अनुकूल थी तो प्रसन्नता का प्रवाह चल पड़ा। वहीं दूसरी घटना मन के प्रतिकूल थी तो विषण्णता का वातावरण बन गया। जब भोजन अच्छा बनता है तो पत्नी को उसके लिए सौ-सौ साधुवाद दिया जाता है। जब कभी भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता या नहीं लगता तब परोसी हुई थाली को ठोकर भी मार दी जाती है। यह सारा मन का कार्य ही होता है। भोजन सिर्फ भोजन होता है। पदार्थ सिर्फ पदार्थ होता है। उसमें स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट का आरोपण हम स्वयं करते हैं, हमारा मन करता है।

सांस्कृतिक पहचान को कुचलने की कुचेष्टाएं कब तक?

ललित गर्ग

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विरासत को कुचलने की चेष्टाएं अतीत से लेकर वर्तमान तक होती रही है। बहुत बड़ा सच है कि अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दो। देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने यही किया। इस्लामी आक्रांताओं ने न सिर्फ धन-संपदा लूटी बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ कर मस्जिदें बना दीं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के शत्रु एवं तथाकथित धर्म-निरपेक्षता की राजनीति करने वाले नेता इस बात को अधिक बेहतर समझते हैं, अतः उन्होंने इतिहास को झुठलाने, धुंधलाने और काल्पनिक बातें गढ़ने एवं फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे नेताओं-नीतिकारों की नासमझी के कारण ही इसमें वे सफल भी रहे हैं। क्या यह स्थिति बदल रही है? देश में कुछ लोग सही इतिहास को उजागर करने एवं ऐतिहासिक विरासत को धुंधलाने एवं कुचलने की कुचेष्टाओं का परिमार्जन करने के लिये तत्पर हुए है, इसी का परिणाम है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल और अजमेर दरगाह जैसे मामलों में साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को हासिल करने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे प्रयासों के द्वारा अशांति फैलाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इतिहास बड़ी भूलों को सुधारना एवं वास्तविक तथ्यों को सामने लाना है। लेकिन, इसमें एक बड़ी बाधा है पूजा स्थल अधिनियम, 1991, जो देश में आजादी से पहले से मौजूद धार्मिक स्थलों जुड़े तथ्यों की खोजबीन की भी अनुमति नहीं देता है? क्या इसके चलते देश में आक्रांतवादी सोच एवं देश की विरासत को धुंधलाने की कोशिश पर पर्दा ही पड़ा रहेगा? ऐतिहासिक अन्याय, अत्याचार एवं राष्ट्र-विरोधी सोच एवं सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। इस देश में उन विघटनकारी एवं संस्कृति-विरोधी लोगों की मर्जी कब तक चलती रहेगी? कब तक बात-बेबात हंगामा होता रहेगा? कब तक सांस्कृतिक पहचान को बेमानी साबित करने के षडयंत्र होते रहेंगे?

इस सच से इंकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास से न केवल छेडछाड़ हुई है बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को निस्तेज भी किया गया है। इसी बात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उजागर करते हुए कहा कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अतीत में यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, यह बात पूर्व में भी बार-बार अनेक नेताओं ने कही है, लेकिन इतिहास को सही रूप में पेश करने का काम नहीं हो पा रहा है और वह भी तब, जब सभी इससे परिचित हैं कि सच्चे इतिहास की जानकारी के अभाव में लोगों के बीच नासमझी की खाई चोड़ी ही होती है, झूठे इतिहास को ही लोग सच मानने से उनकी अपनी परम्परा एवं इतिहास के प्रति आस्था की बजाय घृणा बढ़ती है। अपनी इतिहास एवं संस्कृति की विलक्षण एवं विशेषताओं से दूरी बनाकर झूठे इतिहास के कसीदें पढ़ने से राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव क्षीण होता है। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय एकता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के गौरवपूर्ण क्षण कैसे सामने आ सकते हैं। झूठे इतिहास के कारण लोग संगठित कैसे हो सकते हैं? उनके स्वर विपरीत ही होते हैं, जिससे एक-दूसरे से जुड़ना तो दूर आपसी द्वेष, नफरत एवं द्वंद्व की स्थितियां ही राष्ट्र पर हावी होती है। सही इतिहास जानने की इस महत्ता से हमारे नीति-निमार्ता अनभिज्ञ रहे हैं। अन्यथा इस विषय पर यहां इतनी दलबंदी न होती। हमें एक असहिष्णु, उन्मादी एवं कट्टरवादी समाज बनने के रास्ते पर ही नहीं, बल्कि भीतर से ज्यादा से ज्यादा विभाजित एवं कमजोर समाज बनने के रास्ते पर धकेला जा रहा है। इस तरह की स्थितियां एवं मुहिमें देश की एकता एवं अखण्डता पर आघात करती है।

भारतीयों ने गणित व खगोल विज्ञान पर प्रामाणिक व आधारभूत खोज की। शून्य का आविष्कार, पाई का शुद्धतम मान, सौरमंडल पर सटीक विवरण आदि का आधार भारत में ही तैयार हुआ। वसुधैव कुटुम्बकम का विचार इसी देश ने किया। अहिंसा यहां की जीवनशैली का सौन्दर्य रहा है, विविधता में एकता को हमने जीकर दिखाया है, लेकिन हमारी उदारता को आक्रांताओं एवं विभाजनकारी ताकतों ने हमारी कमजोरी मान लिया है। यही कारण है कि तात्कालिक एवं अतीत की कुछ नकारात्मक घटनाओं व प्रभावों ने जो धुंध हमारी सांस्कृतिक जीवन-शैली पर आरोपित की है, उसे सावधानी पूर्वक हटाना होगा। आज आवश्यकता है कि हम अतीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजें और सवारें तथा उसकी मजबूत आधारशिला पर खडे.होकर नए मूल्यों व नई संस्कृति को निर्मित एवं विकसित करें। ऐसा करके ही हम नया भारत-सशक्त भारत निर्मित कर पायेंगे। समृद्ध संस्कृति भारत की एक विरासत है। इसमें धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त क्रियाएं और कार्य हैं जो उसे महान बनाती है। समय-समय पर इसका विविध संस्कृतियों के साथ संघर्ष, मिलन, परिवर्तन, परिवर्धन और आदान-प्रदान हुआ है। भारतीयों की अनेक भावनाओं पर शताब्दियों से समय-समय पर आती रहने वाली विविध जातियों ने बहुत पहले से ही अपना न्यूनाधिक प्रभाव डाल रखा था। परंतु इस्लाम के आ जाने पर भारतीय संस्कृति में एक हलचल सी मच गयी, सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने के सलक्ष्य प्रयत्न हुए, कला, धार्मिकता, शिल्प के मन्दिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण कराया गया। लेकिन इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का अवकाश तो हमेशा से रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने संभल मस्जिद मामले में 29 नवंबर 2024 को स्थानीय अदालत की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। इस मामले में विपक्षी दल विशेषतः कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश सरकार को जबरन घसीट रही है, जबकि सर्वोच्च अदालत शांति बनाये रखने के लिये मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। 24 नवंबर को अदालती निर्देश पर हुए सर्वे के दौरान खूनी हिंसा, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसका मर्म यह है कि मामले में फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सच है या फिर कौन समुदाय कितना उपद्रव करता है और वह शासन-व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। अर्थात चाहे ह्यअन्यायह्न कितना भी बड़ा हो, अदालत ह्यन्यायह्न से अधिक ह्यशांति-सद्भावनाह्न को वरीयता देगी। देरसबेर न्याय होता हुआ देखा भी गया है, अयोध्या में बना श्रीराम मन्दिर इस का उदाहरण है।

लंबित मामले : अदालतों के मर्म को समझना होगा

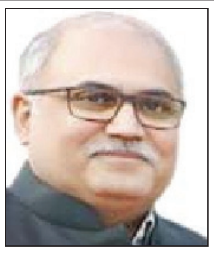

रजनीश कपूर

हमारे देश में जब-जब सरकारी तंत्र फेल होता है तो उसके खिलाफ कोई न कोई अदालत का रुख कर लेता है। इस उम्मीद से कि संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों के हित में यदि कोई फैसला कर सकता है तो वह न्यायपालिका ही है, परंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि जहां देश भर की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित पड़े हैं, वहां सरकारी तंत्र के काम न करने के कारण अदालतों पर अतिरिक्त मुकदमों का ढेर लगता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा जिस कारण नागरिकों को कोर्ट का रुख करने को मजबूर होना पड़ता है?

जब भी किन्हीं दो पक्षों में कोई विवाद होता है तो उनका आखिरी वाक्य होता है कि 'आई विल सी यू इन कोर्ट।' परंतु हमारे देश के न्यायालयों में लंबित केसों की संख्या इतनी ज्यादा है कि न्याय मिलते-मिलते या फैसला आते-आते बहुत देर हो जाती है। ऐसे में कोर्ट में हर दिन बढ़ने वाले मामलों की संख्या पर रोक नहीं लग पा रही। विवाद चाहे किसी की जमीन-जायदाद का हो या अन्य किसी मामले का हो। वादी-प्रतिवादी सीधा कोर्ट का रुख करते हैं और कई मामलों में तो वकील भी अपने मुवक्किल को गुमराह करने में पीछे नहीं हटते। ऐसे में किसी न किसी कारण से न्याय मिलने में देरी हो जाती है। बीते कुछ वर्षों से न्यायपालिका पर काम का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ने का एक और कारण है कि सरकारी तंत्र में तैनात कई अधिकारी, जो अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करने की नीयत से, देश की जनता के साथ धोखा करते हैं। वे संविधान को एक तरफ रख कर अपने राजनैतिक आकाओं को भी गुमराह कर उनसे कुछ ऐसे फैसले दिलवा देते हैं जो जनता के हित में नहीं होते। केवल निहित स्वार्थ के लिए लिए गए ऐसे फैसले राजनैतिक रूप से अक्सर घातक साबित हो जाते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा कर जनता को असल मुद्दों से भटकाने का काम करने लगते हैं। अंततः दोनों में से एक पक्ष अदालत का रुख कर लेता है। ऐसे में अदालतें सरकारी तंत्र के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्राथमिकता पर सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। गौरतलब है कि यदि किसी लंबित मामले में कोई अहम सुनवाई की तारीख लगी हो और उसी बीच कोर्ट के सामने कोई ऐसा 'राजनैतिक' केस आ जाए जिसे, सुनने के लिए उस अदालत को अपनी पहले से तय सूची में फेर-बदल करना पड़े, तो सोचिए कि न सिर्फ अदालत के कीमती समय और पैसे की बबार्दी होती है, बल्कि अदालत में न्याय की उम्मीद कर रहे फरियादी की हिम्मत और न्यायपालिका पर भरोसा भी डगमगाने लगता है।

सोचने वाली बात यह है कि सरकारी मशीनरी अपना काम जिम्मेदारी से करे तो अदालतें भी अपना काम बिना किसी विघ्न के करने लगेंगी। ऐसे में लंबित करोड़ों मामलों में भी गिरावट आएगी। आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि यदि किसी राजनैतिक दल को उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए किसी खास फैसले से एतराज होता है, तो वे उसमें कोई न कोई कमी निकाल कर देश भर में एक नया विवाद पैदा करने में कसर नहीं छोड़ते। फिर वो मामला चाहे किसी विशेष कानून को लेकर ही क्यों न हो।

गौरतलब है कि जब ऐसे किसी विधेयक को संसद में पास करके कानून बनाया जाता है, तो उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस पर चर्चा करते हैं, और यदि कुछ संशोधन करना हो तो उसे करके ही कानून का रूप दिया जाता है। ऐसे में यह माना जाए कि उस समय की विपक्षी पार्टी ने भी ऐसे विधेयक को अपनी सहमति प्रदान की है, लेकिन जैसे ही उस समय की विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है, तो उसी कानून का विरोध करने लगती है, और देश में उथल-पुथल का माहौल बन जाता है, लेकिन क्या वह राजनैतिक दल इस बात पर ध्यान देता है कि उसने विपक्ष में बैठे हुए क्या इस कानून का विरोध किया था? यदि नहीं तो आज ऐसा क्यों कर रहा है? उस कानून के खिलाफ अराजकता फैला कर उसे क्या मिल रहा है? वहीं ऐसे विवादों में बात-बात पर अदालतों का रुख करने वाले याचिकाकर्ता के राजनैतिक संबंधों की जांच होना भी जरूरी है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अदालत में पहुंचने वाला जनहित का मामला क्या वास्तव में 'जनहित' का है या 'निजहित' का?

यदि यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई याचिकाकर्ता जनहित की आड़ में किसी राजनैतिक दल के निजहित में याचिका कर रहा है, तो ऐसी याचिका को देश की किसी भी अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाए। किसे क्या पता कि ऐसे संवेदनशील मामले देश में कैसी आग लगा दें। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र को सही-सलामत रखने के लिए लोकतंत्र के हर स्तंभ को मिल-जुल कर ही काम करना चाहिए न कि किसी विशेष समुदाय या राजनैतिक दल के हित में रह कर। यदि ऐसा होता है तो शायद हम अपने संविधान के मूल ढांचे का पालन कर पाएं। (लेख में विचार निजी हैं)

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Hope for a reset in Akali politics

DECEMBER 2, 2024, will be remembered as an important day in the contemporary history of the Sikhs and the regional politics of Punjab. It saw the Sikh religious seat of power, the Akal Takht, reasserting its authority over the Shiromani Akali Dal (SAD). The five Jathedars summoned nearly the entire party leadership, asking it to admit the criminal misdeeds (gunaah) it had committed while in power and seek forgiveness. Speaking clearly and sharply, they highlighted these 'misdeeds' and how they had seriously hurt the Sikh sentiment, interests and wellbeing. Perhaps the most serious of these misdeeds, they proclaimed, had been their indifference and glaring failure to prevent incidents of disrespect (be-adabi) for the Guru Granth Sahib.

The 'main accused' who appeared before the Takht was former SAD president Sukhbir Singh Badal. But he was not the only one who was held responsible for the criminal wrongdoings. The Jathedars asked all those who had worked with him while he was the Deputy Chief Minister of Punjab to also own up to their involvement and seek forgiveness. They also held the late Parkash Singh Badal, then Chief Minister, equally responsible for these misdeeds and withdrew the honour of Panth Rattan Fakhr-e-Quam bestowed upon him by the Takht in 2011.Given the nature of their authority, the Jathedars pronounced a range of nominal punishments for all those found 'guilty', which the accused 'humbly' accepted. They also directed that the SAD be dissolved, along with its parallel or dissident offshoots. The Jathedars announced the formation of a committee and assigned it the task of rebuilding the political party.The Sikh political system, as we know it today, evolved during the 1920s as an offshoot of the popular movement for the liberation of historic gurdwaras from the control of 'corrupt mahants'. The movement came up with the idea of managing gurdwaras democratically through a body to be elected by common Sikhs, which came to be known as the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC). It was under the aegis of the SGPC that the SAD came into being as its political wing. The colonial state gave it formal recognition in 1925 as the sole custodian of all historic gurdwaras of Punjab. The SGPC continues to have legal status in independent India.

The history of the Akal Takht, the throne of the timeless one, goes back to the sixth Guru, who established it as a seat of temporal authority (miri), facing the Darbar Sahib (often referred to as the Golden Temple), the seat of its spiritual authority (piri). The Takht became the site for the Sikhs to assemble and discuss the political challenges facing the community. After its formation, the SGPC appointed five Jathedars to collectively deliberate upon and decide on issues of politics and justice.Over the years, the electoral political process acquired a kind of autonomy and ascendancy over Sikh religious institutions. The SAD emerged as the power centre and its leadership started controlling the affairs of the SGPC as well. Though members of the General House of the SGPC are separately and independently elected by the Sikh electorate, they have tended to be subservient to their political bosses in the SAD. This became most pronounced between 2007 and 2017, when the SAD ruled the state in alliance with the BJP, with the senior Badal as the CM.It was also the time when the SAD formally acquired a 'secular' character, claiming to be a party of all Punjabis. From a Panthic party of the Sikhs, it began to represent itself as a regional party of Punjab, similar to its counterparts in other regions of India. Its organisational character also changed. From a cadre-based party of the Sikh Sangat, it turned into a family-centric party with a limited social base among the agrarian classes/castes of the state.

Israel scrambles for support to counter ICC arrest warrants

Contrary to the bravado displayed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his advisers on the arrest warrants issued by the International Criminal Court (ICC) on November 21, there are indications that they were worried at that possibility even earlier,..

Contrary to the bravado displayed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his advisers on the arrest warrants issued by the International Criminal Court (ICC) on November 21, there are indications that they were worried at that possibility even earlier, in April this year, and were trying to prevent it by enlisting other powers' support.

On April 19, 2024, The Times of Israel, quoting Channel 12, said that an "emergency discussion" was held at the Prime Minister's Office to decide how to "fend off" the potential warrants. The paper also said that Netanyahu had raised this possibility with visiting Britain Foreign Secretary David Cameron and Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock and "sought their help".

The same paper said on April 28 that Netanyahu was "under unusual stress" over the prospect of an arrest warrant against him by the ICC "which would constitute a major deterioration in Israel's international status." Hence, steps were taken to give a "rare briefing on Shabbat" to the international media through Israeli Defence Force (IDF) spokesman Nadav Shoshani on the government's support to the American-sponsored temporary humanitarian pier off Gaza.Their worry was heightened when another UN body, the International Court of Justice (ICJ), started hearing the genocide case against Israel, launched by South Africa on December 29, 2023. Two hearings in the case were held on January 11 and 12, 2024.

The ICJ, the principal judicial organ of the United Nations (UN), was established in 1945 under the UN charter for adjudicating disputes between states and fixing responsibility of a state under international law after inquiring whether a state party to the case has breached it. It can issue "provisional measures" to preserve those rights until the case proceedings are completed. In this case, provisional orders to prevent and punish incitement to genocide and to allow relief materials were passed on January 26, 2024.On July 19, 2024, the ICJ, in a different context, gave its advisory opinion that Israel's occupation of the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, along with the associated settlement regime, annexation and use of natural resources was unlawful. This was on a reference made by the UN General Assembly in 2022. The ICJ mandated Israel to end its occupation, dismantle its settlements, provide full reparations to Palestinian victims and facilitate the return of displaced people.The ICC, established in 2002 by the "Rome Statute", is different from the ICJ as it seeks to establish individual criminal responsibility for serious international crimes. Through its

prosecutor, who has the power to carry out investigations of crimes within the jurisdiction of the ICC, the court can issue arrest warrants for individuals.

Israel is in a bind as it had signed the Rome Statute on December 31, 2000, after considerable reluctance, although in the 1940s, the Jews were ardent supporters of such a court, having suffered under the Nazi regime. The procedure is that either the UN Security Council or any of the 124 member states of the Rome Statute can refer a situation to the court, asking the prosecutor to conduct a preliminary investigation. The prosecutor can also launch an investigation on his own initiative.

The court does not have a police force, but all states that have signed are obliged to comply with a requested arrest warrant. Hearings are conducted as a criminal trial, with prosecution and defence counsels before a tribunal of judges.

Israel complained to the ICC on October 5 that its prosecutor Karim Khan did not give it an opportunity to investigate "his allegations before seeking arrest warrants against its leaders, which was a fundamental principle of the ICC's founding charter."ccording to it, the prosecutor should have, under Article 18 of the Rome Statute, provided "sufficiently specific information to the state under investigation about the crimes that they are investigating" to examine whether that country was willing to launch prosecutions against the errant individuals.It alleged that Khan relied upon a 2018 notification sent to Israel about alleged crimes "relating to Israeli settlement policy and claims raised in previous hostilities in Gaza" and not on the Israeli operations consequent to the Hamas attack on October 7, 2023. US Secretary of State Antony Blinken and two US senators supported this, saying that Khan "rushed" to get the warrants "to politically target Israel."As things stand, it is not clear what the signatories, especially from Europe of the Rome Statute, would do. America, Israel, Russia, China and India have not ratified the Rome Statute. President Joe Biden has said that America had rejected the ICC decision. Incoming Republican leader John Thune has urged the Senate to pass a Bill that was cleared by the House of Representatives, under which the US would impose sanctions on people "engaged in any effort to investigate, arrest, detain or prosecute any protected person of the United States and its allies."

There are many imponderables here. While Britain, supported by EU's foreign policy chief Josep Borrell, originally said that it would honour the treaty obligations, there are reports that France is reconsidering its earlier stand by Prime Minister Michel Barnier that the country was bound to abide by all treaties.On November 27, Israeli newspaper Haaretz quoted the Quai d'Orsay (French foreign office) to reveal that Netanyahu and Yoav Gallant could be entitled to immunity from arrest warrants issued by the ICC. This was after the Israel-Lebanon ceasefire, helped by French President Emmanuel Macron.

At the same time, western powers led by America are apprehensive that any dilution of the ICC's powers might boomerang on the ongoing investigations against Argentina and Russia, which they want to pursue.

Cost of freebies

BOTH Punjab and Himachal Pradesh are reeling under severe financial stress, a crisis stemming from populist promises made during electoral campaigns. In Punjab, the Aam Aadmi Party's (AAP) commitment to provide 300 units of electricity free of cost to the...

BOTH Punjab and Himachal Pradesh are reeling under severe financial stress, a crisis stemming from populist promises made during electoral campaigns. In Punjab, the Aam Aadmi Party's (AAP) commitment to provide 300 units of electricity free of cost to the consumers has resulted in a subsidy bill of over Rs 20,000 crore for the current financial year. Himachal, where the Congress is in power, revived the Old Pension Scheme (OPS), adding a significant burden to an already strained exchequer.

Punjab's predicament is worsened by delayed subsidy payments, with the pending bill crossing Rs 4,500 crore. The Punjab State Power Corporation Limited is struggling with a dip in collection efficiency, dropping from 106% to 73%, and soaring transmission losses. Attempts to raise revenue, including recovering dues from defaulters and government departments, have yielded little relief. With the state

nearing its borrowing limit, the sustainability of the free electricity scheme is under question. Himachal Pradesh faces a similar plight. The restoration of OPS has inflated the state's financial obligations, requiring Rs 2,000 crore monthly to meet salary and pension commitments. Exhausting its loan limit of Rs 6,200 crore, the state is now relying on future borrowings to manage day-to-day expenses. The situation is set to worsen as the Centre's revenue deficit grant is expected to be halved next fiscal year.

Both states accuse the BJP-led Centre of withholding funds and showing a discriminatory attitude. Himachal's exclusion from the Special Assistance for Capital Investment Scheme has sparked a political outcry, while Punjab alleges bias in the allocation of development funds. However, the root cause lies in unsustainable fiscal policies driven by electoral populism. As state governments grapple with mounting debt and shrinking revenues, it is imperative to shift focus from doles to structural reforms. Fiscal prudence, efficient tax collection and targeted subsidies are the need of the hour.

Centre must aid states on new criminal laws

Making rules for ensuring the implementation of a number of new concepts, as envisaged in the BNSS, is the key to success.

PRIME Minister Narendra Modi dedicated the successful implementation of the new criminal laws to the nation at a grand function in Chandigarh on December 3. Home Minister Amit Shah complimented the Chandigarh police for being the first unit to enforce the new legislations, and meticulously. He hoped that the laws would become operational fully throughout the country within three years — the time needed to create infrastructure and integration of database with several portals for the purpose of coordination between the various wings of the Criminal Justice System (CJS), which are time-consuming processes.The Home Minister stated that 11,34,698 policemen had been imparted training and more than 11 lakh criminal cases registered after July 1, 2024 under the new provisions of laws; 9,500 of them had already been decided upon. Such is the impact of these new procedures that the Chandigarh police have achieved 85 per cent conviction rate in the cases decided following the new scheme.

It was a historic moment for the people to be witness to the new-era penal legislations adopting the Indian soul, which subscribed to the people-centric and justice-oriented approach. They replaced the colonial laws as standposts of suppression and retribution, said the PM.The occasion offered an opportunity to the professionals in the field of justice delivery to undertake an operational audit of the working of the new laws to identify bottlenecks and shortcomings and suggest measures for credible performance in future. It is said that laws do not operate in isolation.

Police investigating officers have started applying the new sections of the criminal laws in all cases. The successful implementation, though, would mean much more than that. It requires the creation of electronic and digital infrastructure and the recruitment and training of staff for the proposed digitalisation of CJS. The enactment of a large number of subordinate legislations by the states in the form of rules, operating procedures, forms and formats, etc is essential to bring the laws in full operation. Upgrading of the software relating to Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) and Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) for linking between the stakeholders is necessary for proper coordination between the enforcers. Making rules for ensuring the implementation of a number of new concepts, as envisaged in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), is the key to success.Implementing provisions relating to the e-registration of first information report (FIR), e-service of summons and warrants, zero FIR, witness protection schemes, community service, trial in absentia, seizure and forfeiture of proceeds of crimes, time-bound disposal of case properties, sharing of forfeited proceeds of crimes with the victims of crimes, commutation of sentence, storing of videography footage, etc would not be a reality unless the operational protocols and rules are framed by the states immediately. In their absence, these novel concepts would remain on paper only.

The Home Minister called the forensic experts the 'fifth pillar of CJS.' The network of forensic science

laboratories (FSLs) is scanty. To ensure mandatory visits of forensic experts on all scenes of crimes entailing punishment of more than seven years, as per the new laws, the FSLs would require extension up to the police station level. Given the limited availability of forensic experts, it is a huge task.Integrating the main pillars of criminal justice — the police (CCTNS), courts (e-courts), jails (e-prisons), forensic lab (e-forensic) and prosecution (e-prosecution) — through the ICJS is a Herculean task. The work has just begun. It cannot be completed unless all other related works falling in the domain of state agencies is accomplished.

The time-bound disposal of case properties is a welcome feature of the new procedural law. Unfortunately, this provision had not found favour with the courts till now — perhaps, for want of urgency on the part of law enforcers or due to lack of infrastructure.One of the striking features of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, (BNS) is contained in Section 48, which criminalises the abetting of offences in India by terrorists and gangsters sitting in foreign countries. Section 107 of the BNSS provides for the forfeiture of the proceeds of crimes. Section 356 of the BNSS pertains to the concept of 'trial in absentia' for bringing absconders of law to justice. It is intriguing that none of the criminals operating from outside the country could be nailed down under these provisions so far.Community service as a sentence is included in the list of punishments under the BNS, but no identified apparatus and protocols are in place to execute it. Moreover, the sentence of community service has just a cosmetic effect in the new criminal laws as offenders involved only in six petty crimes out of all the offences contained in the BNS are punishable with this sentence. There is a need to extend the scope of this punishment for all first-time petty offenders. Some other noticeable anomalies are also there in the new laws, which need appropriate resolution.

Markets Face Volatile Trends After RBI Policy Announcement

The 30-share BSE benchmark Sensex declined 259.67 points to 81,506.19 soon after the announcement. The NSE Nifty also went lower by 87.9 points to 24,620.50.

Mumbai. BenAchmark equity indices Sensex and Nifty turned highly volatile trade after the Reserve Bank of India's monetary policy announcement.

The 30-share BSE benchmark Sensex declined 259.67 points to 81,506.19 soon after the announcement. The NSE Nifty also went lower by 87.9 points to 24,620.50.The Reserve Bank of India (RBI) maintained the status quo on interest rate despite July-September quarter GDP growth falling to 7-quarter low of 5.4 per cent, as against its own projection of 7 per cent.The rate increase cycle was paused in April last year after six consecutive rate hikes, aggregating to 250 basis points since May 2022.Announcing the fifth bi-monthly monetary policy for the current financial year, RBI Governor Shaktikanta Das said the Monetary Policy Committee (MPC) has decided to keep the repo rate unchanged at 6.5 per cent while keeping policy stance unchanged at neutral.

The RBI sharply cut the GDP growth projection to 6.6 per cent from the earlier level of 7.2 per cent, while raising inflation target to 4.8 per cent from the previous projection of 4.5 per cent for the current fiscal.In a bid to make available more money with banks for lending so as to boost economic activity, the RBI slashed Cash Reserve Ratio to 4 per cent from existing 4.5 per cent. This would lead to release of Rs 1.16 lakh crore to banks and improve their lending capacity.

The CRR is the percentage of a bank's total deposits that it is required to maintain in liquid cash with the RBI."Monetary policy has delivered exactly what the

economy and markets need in the present context. The governor's emphasis on price stability is appropriate given the elevated level of inflation. The decision to cut the CRR by 50 bps facilitating injection of Rs 1.16 trillion of liquidity into the system will ease the liquidity constraints and more importantly reduce the banks' cost of funds. From the market perspective, this is an excellent policy response. Banking stocks will remain resilient," V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services, said.From the 30-share pack, Infosys, UltraTech Cement, Tata Motors, Hindustan Unilever, Tata Consultancy Services and Asian Paints were among the laggards.Axis Bank, ITC, Larsen & Toubro, Titan, State Bank of India and Power Grid were among the gainers.Foreign Institutional Investors (FIIs) bought equities worth Rs 8,539.91 crore on Thursday, according to exchange data.

In Asian markets, Seoul and Tokyo were trading lower while Shanghai and Hong Kong quoted in the green.US markets ended lower on Thursday.Global oil benchmark Brent crude dipped 0.04 per cent to USD 72.05 a barrel.Rallying for the fifth day running, the 30-share BSE benchmark jumped 809.53 points or 1 per cent to settle at 81,765.86 on Thursday. The Nifty surged 240.95 points or 0.98 per cent to 24,708.40.

You May Soon Draw PF Money Through ATMs; Amazing Feature Likely Coming In EPFO 3.0 Next Year

New Delhi. In order to improve services for EPFO members, the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) intends to update to a new version, EPFO 3.0. One of the most significant aspects of EPFO 3.0 is that subscribers will get the option to withdraw Provident Fund (PF) from ATMs, ET Now has reported.To make withdrawals easier, the EPFO is coming up with a new initiative that will allow subscribers to withdraw their PF money directly from the ATMs, ET Now has said. An ATM card, akin to a debit card, would be issued by the labour ministry to enable members to take out PF money directly from ATMs. Nevertheless, the maximum amount that can be taken out will be 50% of the entire deposit. This feature might be implemented somewhere between May and June of 2025, it added.At the moment, it takes seven to ten days for the withdrawal amount to be credited to the bank account that is linked to the EPF account. The updated feature will streamline the withdrawal process by enabling members to take out their PF amounts straight from ATMs.The prevailing 12% contribution cap may be lifted by the government. This will allow employees to contribute as much amount as they want. On the other hand, the employer's contribution will be fixed based on the employee's salary, and therefore the employer will not be burdened.

Vishal Mega Mart's Rs 8,000 crore public offer to open on December 11

MUMBAI. Leading supermarket player Vishal Mega Mart's Rs 8,000 crore initial public offer will be opening on December 11.

The company is yet to announce the price band for the mega issue.The issue is entirely offer for sale (OFS) by promoter Samayat Services, and has no fresh issue of shares, therefore, no money from the issue will go to the company, according to the final IPO papers filed with the capital market regulator Sebi on Thursday.Currently, Samayat Services holds 96.55% stake in the Gurugram-based supermart major. Vishal offers apparel, general merchandise and fast-moving consumer goods (FMCG) categories through its 626 stores and the mobile application and website.Vishal Mega Mart competes with Mukesh Ambani's Reliance Retail, Tata Group's Trent and grocery retailer Avenue Supermarts, which runs the D-Mart labelled supermatkers chain and is owned by leading stock broker Damani, among others. Vishal is among the two leading offline-first diversified retailers in terms of same-store sales growth.

The updated draft filing was filed in October after Vishal's confidential offer document was approved by Sebi late September. The company filed its offer document in July through the confidential pre-filing route.The retailer had strong financial performance in the past years, with consolidated net in financial year 2023-24 growing 43.8% to Rs 461.9 crore on a revenue of Rs 8,911.9 crore, a growth of 17.5% over financial year 2022-23.

New credit card issuances plunge 50% in October to 7.8 lakh as against 16 lakh a year ago

MUMBAI. The credit card industry seeing a sharp 50% year-on-year decline in new card issuances to a meagre 7.8 lakh in October as against 16 lakh cards issued in the same month last year.In November 2023, the Reserve Bank, fearing a bubble build-up in the unsecured loans segment, which has been growing at three times the other loans for nearly two years, asked credit card issuing banks to set aside 25 percentage points more money as risk capital, taking the total to 150%.Still, banks continued to aggressively push credit cards and since the second quarter almost all lenders have begun to report higher delinquencies. The worst affected ones are Kotak Mahindra Bank, RBL Bank, and Axis Bank, among others.Domestic brokerage Anand Rathi

stated that the industry; led by HDFC Bank with about 24% market share followed by SBI Card with close to 20%, ICICI Bank and Axis Bank; has added only 7.8 lakh new credit cards in October. May 2024 was the lowest in many years when the industry added just 7.6 lakh customers.But on an annualised basis, the October numbers as much as 45% less than what the industry did last year.Despite this decline, net additions in October 2024 were higher than in June 2024, contributing to a 16% quarter-on-quarter rise in cards in force, the report said.The report also highlights the total spending through credit cards reached Rs 1.78 trillion in October 2024, reflecting a 13% YoY growth.According to the report, the share of the e-commerce segment in total spending value dropped to 61% in October from 65% in September, while point of sale transactions saw its share rising to 39% from 35% in the previous month.PoS and e-commerce volumes continued to move in favour of the former, now nearly 51%, while the latter's share declined to about 49%, while in terms of transaction volume, the preference continued to move towards PoS transactions, which now account for nearly 51% of total credit card transactions.

CEA calls for striking balance between corporate profitability, workers' income

The CEA emphasised on private sector large heartedness and the role corporates can play in propping up consumption.

NEW DELHI. The anemic growth in private consumption has started to give jitters to the government as the chief economic advisor (CEA) to the Ministry of Finance Dr V Anantha Nageswaran on Thursday called for a balance between corporate profitability and workers' income growth.

Speaking in an event organized by Assocham, the CEA noted that even as corporate profitability was at a 15-year high in FY24, much of this income was diverted by companies to reduce their leverage. He expressed concern that workers' salaries have not grown commensurate with corporate profitability."While it is good to improve balance sheets, corporate profitability and workers' income growth has to be balanced, without this parity, there will not be adequate demand in the economy for corporate products to be purchased," said Nageswaran. The CEA emphasised on private sector large heartedness and the role corporates can play in propping up consumption."If consumption has to drive economic growth, then we must look at the post-Covid hiring trends, where there has

been a shift to contractual labour. While these contracts are formal in nature – the workers receive employee benefits like provident fund and health insurance etc – but the wage growth for contract employees have not kept up with inflation," CEA Nageswaran said.

CEA's statement assumes significance as second quarter GDP growth in the current financial year fell to a 2-year low of 5.4% primarily because of slow private consumption and capex growth. In the second quarter, private consumption grew by 6%, down from 7.4% in the previous quarter. The Q-o-Q drop in consumption was despite a low base of 2.6% growth in the same quarter previous year.

Most FMCG companies had raised the issue of slowness in consumption growth due to very high inflation and stagnant wages. Many FMCG companies pointed out that they have been witnessing slow volume growth and in some even contraction

Bitcoin beats regulatory hurdles, hits $100K level

NEW DELHI. Despite regulatory uncertainties around the globe, Bitcoin prices on Thursday breached the psychologically important level of $100,000, surging nearly 133% over the last one year. The rise in cryptocurrency was hastened by the victory of Donald Trump in the US presidential election.

Bitcoin prices have risen by over 50% since the US presidential Election Day (5 November 2024) in anticipation that the Trump administration will ease regulatory hurdles and create a more favourable environment for digital assets. The market cap of Bitcoin is now a massive $2 trillion.The rise in Bitcoin prices beyond $100,000 mark is a testament to the resilience and adoption of Bitcoin, says Sumit Gupta, co-founder, CoinDCX.

"The psychological breakthrough will prompt institutions, companies, and countries to take Bitcoin and crypto more seriously. Retail investors may now view it as a validated, stable asset class, and we could see deeper integration of bitcoin into mainstream investment products," added Gupta.Bitcoin is the first decentralised cryptocurrency invented in 2008 by a yet unknown person named Satoshi Nakamato. Its use began in 2009. Ever since, bitcoin prices have seen many ups and downs with bouts of heart-stopping volatility.

Yet over the long-term, the digital currency has given eye-popping returns. In the last five years, prices of Bitcoins have surged 1,263% or 13 times its price. "This growth is still shy of the levels we experienced during the peak of 2021, underscoring the untapped potential in the ecosystem as we steadily move toward brighter times," says Balaji Srihari, business head, CoinSwitch.

The surge in Bitcoin prices in the last one month has also had a rub-off effect on other cryptos. Ethereum prices have jumped 60% in the past one month and 2,500% in the past five years. Market cap of Ethereum is closing in on $500 billion mark. Other tokens such as Solana and XRP have hit an all-time high.

The regulatory uncertainty, however, will continue to make bitcoin a risky investment option, especially for retail investors. In India, the government has not yet taken a call on complete ban of cryptocurrencies despite the Reserve Bank of India's persistent demand for a ban. Reserve Bank of India governor Shaktikanta Das has on several occasions termed the digital currency as a threat to financial sovereignty of the country.

The Indian government has, however, tried to disincentivise investment and trading in cryptocurrencies by levying 30% tax on capital gains and 1% tax on transactions in cryptos.

Trump tariffs: Government tries to identify areas of gain

NEW DELHI. With Donald Trump threatening to impose additional duties against China and Mexico, government has launched a multi-pronged exercise, which seeks to identify areas where India can tap into an opportunity but is also keeping close tabs on currency movement.

While the recent depreciation of rupee is seen to be helpful in making Indian goods more competitive, a lot will also depend on how other currencies move. Official sources told TOI that all eyes are on China as a steep depreciation of the yuan could help the Asian giant counter some of the impact of the additional tariffs that the Trump administration imposes.

Since October-end, rupee has weakened around 0.7% against US dollar, while the Chinese currency has seen a near 2% depreciation. Several other currencies have weakened even more. The jury is, however, divided on the extent of China's benefit from depreciation.While govt officials keep tabs on Trump's next set of moves, they are breathing easy as India has not yet figured in the US president-elect's trade war calculations. But, they are not ruling out the possibility of steps coming in the future, which many believe will be a negotiating strategy by the new US administration to get India to offer some concessions to American goods.For the moment, the commerce department is assessing sectors, where India can gain from actions being taken against China, as well as Chinese companies. Textiles, electronics goods and pharma are among sectors, where govt is assessing the capacity that manufacturers in India have and if they can ramp it up to tap into any opportunity in future. Sectors, such as textiles and garments, are seen to be especially lucrative as the recent tension in Bangladesh could also help Indian players.

"We have seen an increase in mobile production in India, which is also catering to export demand. Similarly, there is a need to push the production of laptops and personal computers in In dia, which can also meet demand in other countries, especially as China faces pressure," a senior official told TOI. India will, however, have to compete with countries such as Vietnam to grab a bigger share of the American pie.In last fiscal year, the US was India's largest trading partner with bilateral trade of almost $120 billion. With exports of $77.5 billion, India had a trade surplus of over $35 billion, according to commerce department data. According to US data, India had the seventh highest trade surplus, with Trump's recent threat focused on the top three countries with a favourable balance of trade – China, Mexico and Canada.Government officials have said goods trade numbers need to be looked at along with services, where the US enjoys significant advantages.

RBI Hikes Rate Caps On Diaspora's Foreign Currency Deposits To Attract Flows

According to the BBC report, "Enmetazobactam, developed by Chennai-based Orchid Pharma, is the first antimicrobial invented in India to be approved by the US Food and Drug Administration (FDA)."

Mumbai. The Reserve Bank on Friday announced a raise in the interest rate caps on the diaspora's foreign currency deposits, in a move aimed at attracting more capital flows amid pressures on the rupee.Announcing the fifth bi-monthly monetary policy for the current financial year, RBI Governor Shaktikanta Das said it has been decided to increase the interest rate ceilings on Foreign Currency Non-Resident Bank deposits or FCNR (B) deposits as per tenors.It can be noted that the move comes at a time when rupee has been hitting lifetime lows against the dollar, and the Reserve Bank of India (RBI) seems to be deploying forex reserves to contain the volatilities, as seen in the sharp fall in the kitty over the last few weeks.Starting from Friday, banks have been now permitted to raise fresh FCNR (B) deposits of 1 year to less than 3 years maturity at rates not exceeding Overnight Alternative Reference Rate (ARR) plus 400 basis points, as against 250 basis points earlier.Similarly, deposits with maturity between 3 to 5 years can be paid an interest of ARR plus 500 basis points, as against the 350 basis points ceiling earlier, Das said.The relaxation will be available only till March 31 next year, he said.It can be noted that India, which is the largest beneficiary of remittances in the world, has introduced sweeter deals to NRI deposits in the past episodes of rupee coming under pressure.Das said the rupee has

depreciated by 1.3 per cent mainly on strengthening of the US dollar and selling pressure from foreign portfolio investors in October and November, and added that the volatility was less when compared to peer emerging markets.

Stressing that the RBI's exchange rate policy has been consistent to let the markets determine the levels, Das said foreign exchange reserves are used judiciously to mitigate undue volatility, maintain market confidence and preserve overall financial stability.

Meanwhile, the Governor also announced an Expansion in the reach of forex-Retail Platform through linkages with Bharat Connect on Friday.

Das said with the objective of bringing greater transparency and fairness in the pricing of foreign exchange for users, especially for individuals and the Micro, Small and Medium Enterprises, the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) launched the FX-Retail platform in 2019.Presently, the FX-Retail platform is accessible through an internet-based application, he said, adding that it is proposed to facilitate the linking of the FX-Retail platform with Bharat Connect (earlier known as Bharat Bill Payment System) operated by the NPCI Bharat Connect.

Delhi triple murder: Police recover murder weapon

➤According to the police, Tanwar did not have good relations with his parents, who he claimed favoured his sister Kavita in all aspects of life.

NEW DELHI. Delhi Police on Thursday recovered the murder weapon, an army knife, which was used by a 20-year-old man to murder his entire family of three people in southwest Delhi's Neb Sarai area. Apart from the knife, the police also recovered the blood-stained clothes from a nearby forest which were worn by the accused, said officials.

Twenty-year-old Arjun Tanwar, a second-year BA student at Delhi University, was arrested on Wednesday for allegedly killing his parents and elder sister. Ex-armyman Rajesh Kumar (51), his wife Komal (46) and their daughter Kavita (23) were found dead at their house in Deoli village on Wednesday morning.

According to the police, Tanwar did not have good relations with his parents, who he claimed favoured his sister Kavita in all aspects of life.

The police recovered his blood-stained sweatshirt and the army knife which he used for killing his parents and sister from Sanjay Van late Wednesday night. During interrogation, Tanwar told the police that he first slit his sister's throat who was sleeping on the ground floor.

Then he went to the first floor where he found his father in a deep sleep, while his mother had already woken up and was inside the washroom. Arjun slit his father's throat and moved on to his next target, his mother. As she came out, Arjun first smothered her and then stabbed her neck repeatedly, till she died on the spot. Tanwar then changed his blood-stained clothes, put them in his gym bag and went to Sanjay Van where he dumped the bodies, they added. After returning home, he tried to clean the blood spots in the washroom and other articles in the house, the officials said.

Tanwar then provided a false alibi to the police, claiming he had been at the gym when the crime took place. The accused was a trained boxer. He represented Delhi in a state boxing event, where he won silver.

Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel quits electoral politics

He also assured that he would continue to be part of the party and take on any responsibilities assigned to him.

NEW DELHI. Delhi Assembly Speaker and AAP MLA from Shahdara, Ram Niwas Goel, announced his retirement from active electoral politics on Thursday, citing advancing age as the reason for his decision. Goel, 76, informed AAP national convenor Arvind Kejriwal in a letter, expressing gratitude for the respect shown by party legislators.

He also assured that he would continue to be part of the party and take on any responsibilities assigned to him. In response to Goel's announcement, Kejriwal tweeted, "Ram Niwas Goel's decision to retire from electoral politics is an emotional moment for all of us. His guidance has been invaluable, both inside and outside the House, for many years. Due to his age and health, he had recently expressed his desire to step back from active politics. We respect his decision. Goel Sahab was, is, and will always be the guardian of our family."

Reacting to Goel's retirement, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "Goel has been a staunch supporter of Kejriwal for the last 10 years, but after the party's recent developments, including the entry of Shunty, he had no option but to retire."

Delhi govt to launch AI-powered traffic violation system in April

NEW DELHI. Traffic monitoring through artificial intelligence (AI) enabled automated number plate recognition (ANPR) system in the city is expected to begin at the start of the next financial year.

Officials said that the Delhi government has floated the tender to develop the system for which over a dozen private firms have shown interest so far. While the timeline has not been fixed, the tender allotment and implementation would take about four months, they added.

CCTV cameras equipped with state-of-the-art technology will be installed at 500 places. About 400 of them will be at petrol pumps, while the locations for the rest of them are being worked out.

The firm that will be awarded the tender will create an ANPR violation system on a revenue-sharing model. A command centre will also be set up to analyse the feed and data, so that traffic plans can be made based on the analysis. A part of the revenue earned through fines imposed on violators will be given to the company. The contract with the firm will remain in effect for 20 years.

"Initially, 500 places will be monitored. After this, the number will be increased as per the need," a senior transport department official said.

"Many traffic violations of two-wheeler riders, private cars, cabs, cargo and passenger vehicles can be fined through AI. The traffic police currently challans violators on the spot. Work on the project will start 30 to 45 days after the tender is allotted," the official added.

2020 riots: Delhi HC quashes one of two FIRs against AAP councillor Hussain

NEW DELHI. The Delhi HC has quashed an FIR against former AAP councillor Tahir Hussain, linked to 2020 Delhi riots, citing the existence of a prior FIR covering the same incident.

Justice Subramonium Prasad ruled that the chargesheet filed in the quashed FIR would be treated as a supplementary chargesheet in the earlier case, allowing the trial to proceed without prejudice to the victims.

The court noted that the second FIR, registered on February 27, 2020, detailed allegations of rioting and arson on the first floor of a building, while the first FIR, dated February 25, 2020, pertained to similar offences on the ground floor of the same building."A perusal of the two FIRs shows that the rioters first broke open the

shutters of Pradeep Parking and set fire to vehicles parked there, and then proceeded to the first floor, where they destroyed goods prepared for a marriage ceremony. Both incidents are part of the same episode," the court stated.

Acknowledging that the victims in both FIRs were different, the court emphasised that quashing the second FIR outright could deny justice to the aggrieved parties. It observed that nine eyewitnesses and 23 additional witnesses were common in both cases, ensuring that there was no prejudice if the chargesheet from the second FIR was integrated into the first case.

"The mistake of the prosecution in filing two FIRs for an incident within the same building cannot result in injustice to the victims. This court is inclined to quash FIR 116/2020, dated February 27, 2020, registered at Police Station Khajuri Khas, with a direction that its chargesheet be treated as a supplementary chargesheet in FIR 101/2020," the court ordered.

Delhi HC asks govt to clarify stand on illegal dog breeding, questions lax enforcement

The court is hearing a PIL seeking stringent control over illegal dog breeding in Delhi, a plea that has been pending for six years.

NEW DELHI. The Delhi High Court urged the Delhi government on Thursday to clarify its position on the existence of dog breeders in the city amid allegations of illegal breeding operations.

A bench comprising Acting Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice Tushar Rao Gedela directed the state government to submit a status report detailing measures against violators of the Prevention of Cruelty to Animals Rules, 2017 and 2018.

The court expressed scepticism over the claim that there are no breeders in Delhi, citing the broad definition of "breeders" under the relevant laws. It instructed the Delhi government to file an affidavit explicitly stating its stance and outlining steps to identify and regulate breeders within the National Capital Territory (NCT)."It is contended that there are no breeders in

Delhi, and therefore, no further action is required under the breeding rules," noted the bench.

However, it called for concrete action to substantiate such claims.The government's counsel informed the court that a registration drive for pet shop owners was in progress and expected to conclude within 90 days. Following the registration, authorities would enforce compliance with breeding regulations, and violators - whether registered or not - would face appropriate action.The bench sought an update on the status of this registration exercise and the action plan to address violators. It also instructed the Secretary of the Animal Husbandry Department to file an affidavit detailing measures already taken and the roadmap for future enforcement. The court is hearing a PIL seeking stringent control over illegal dog breeding in Delhi, a plea that has been pending for six years. The bench expressed frustration at the lack of progress, particularly in light of increasing dog bite incidents.

In its previous order, the court directed the Delhi government to disclose a detailed timeline for implementing the Prevention of Cruelty to Animals Rules. Despite repeated directives, it noted that no significant action had been taken.

AAP MLA Naresh Balyan sent to one-day judicial custody in MCOCA case

NEW DELHI. Delhi's Rouse Avenue Court on Thursday sent AAP's Uttam Nagar MLA Naresh Balyan to a day's judicial custody in connection with a case lodged against him under the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) as arguments on the police plea seeking his remand for interrogation remained inconclusive. Earlier in the day, the Dwarka court dismissed the police's application seeking 10 days of custody for Balyan; however, the court rejected it.Additional Sessions Judge Vandana Jain, presiding over the case at the court, rebuked the prosecution for its approach."I do not have the power to transfer the case. Show me a precedent where this has been done. What was the need to come here? This is a sheer waste of my time," said Judge Jain. She granted liberty to the Investigating Officer (IO) to seek custody before the appropriate MP/MLA court. According to the Delhi Police, Balyan is allegedly linked to a crime syndicate led by gangster Kapil Sangwan. The prosecution claimed Balyan facilitated organised crimes, specified targets, and invested money on behalf of the syndicate.

Congress promises free power, auto licences ahead of Delhi elections

➤Delhi Congress president Devender Yadav said that if Congress forms the government in Delhi in 2025, its top priority would be implementing the Tehbazari, the Street Vending Act of 2014.

NEW DELHI. The Congress is making a series of promises to appeal to voters from the lower middle-income class during the final leg of its Dilli Nyay Yatra.

Among the key promises are doubling free electricity units, granting property rights to homeowners in resettlement colonies, implementing the Street Vending Act of 2014, and renewing auto rickshaw licences.

Delhi Congress president Devender Yadav said that if Congress forms the government in Delhi in 2025, its top priority would be implementing the Tehbazari, the Street Vending Act of 2014.

The law, passed by the Congress-led UPA government at the Centre, aims to protect the rights of urban street vendors and regulate street vending activities.

"During the Delhi Nyay Yatra, we came across

thousands of street vendors who shared their struggles with us," Yadav said.

"They complained about facing constant harassment from the police and MCD officials due to the absence of designated vending zones and licenses."

Additionally, Yadav promised to resume the registration of auto rickshaws, providing permits to end black marketing and benefiting over 4 lakh people in the national capital. Currently, 93,654 auto rickshaws are registered in Delhi.

"After AAP's victory in 2014, Kejriwal announced several initiatives, such as increasing auto fares based on inflation, ending police harassment, raising the number of auto permits to one lakh and building at least 300 auto stands across the city. However, Kejriwal failed to fulfill any of these promises, betraying auto rickshaw drivers," Yadav said. On the issue of property rights for residents of resettlement colonies, Yadav stressed that these rights would allow residents to access bank loans for education, marriage, and other necessities. "When Congress was in power in Delhi and at the Centre, we prioritised the welfare of the poor."

Meet Kerala priest George Jacob Koovakad, to become Cardinal in Vatican on Dec 8

Monsignor George Jacob Koovakad, a distinguished priest from Kerala, will be officially elevated to the rank of Cardinal by Pope Francis in a ceremony scheduled for December 8, 2024, coinciding with the Feast of the Immaculate Conception.

New Delhi. Monsignor George Jacob Koovakad, a 51-year-old priest from Kerala, is set to join the prestigious College of Cardinals, one of the highest honours in the Catholic Church. His appointment by Pope Francis underscores a remarkable journey of service, spirituality, and dedication to both the global and Indian Catholic communities. The official ceremony for this elevation will take place on December 8, 2024, coinciding with the Feast of the Immaculate Conception.

A JOURNEY ROOTED IN FAITH AND SERVICE

Born on August 11, 1973, in Thiruvananthapuram, Kerala, Monsignor Koovakad belongs to the Syro-Malabar Archdiocese of Changanacherry, a prominent Catholic community in India. He was ordained as a priest on July 24, 2004, and soon pursued further theological and diplomatic training at the Pontifical Ecclesiastical Academy in Rome. This led him to a distinguished career in the Vatican Diplomatic Service starting in 2006.

A DIPLOMAT FOR THE HOLY SEE

Monsignor Koovakad has served in various Apostolic Nunciatures across the globe, including Algeria, South Korea, Iran, Costa Rica, and Venezuela. His roles ranged from Secretary to Counsellor in these missions. In 2020, he was appointed to the Vatican's Secretariat of State, taking charge of organising Pope Francis's international travels—a critical responsibility in representing the Church worldwide.

A MOMENT OF PRIDE FOR INDIAN CATHOLICS

Monsignor Koovakad's elevation to cardinal is a historic moment for Indian Catholics. It reflects Pope Francis's ongoing efforts to make the Church more inclusive and diverse. Archbishop Thomas Tharayil of Changanacherry hailed him as "a man of spiritual integrity"

and "a dynamic presence in the ecumenical Church." This honour is particularly significant for the Syro-Malabar Church, which rarely sees representation at this level.

A PERSONAL CONNECTION TO POPE FRANCIS

Monsignor Koovakad's close relationship with Pope Francis extends beyond professional duties. In a heartwarming gesture, the Pope personally video-called Koovakad's 95-year-old grandmother, Sosamma Antony, in September 2023, offering blessings and humour during her recovery from Covid-19. This act highlights the deep bond between the Pope and his trusted envoy.

THE CONSISTORY AND ITS GLOBAL IMPACT

The consistory on December 8 will see 21 new cardinals, with representatives from diverse countries, including Japan, Brazil, Canada, and the Ivory Coast. Monsignor Koovakad, as one of the youngest cardinals, will also be eligible to vote in the next papal conclave, influencing the future direction of the Church. This is a reflection of Pope Francis's vision to bring fresh perspectives and reforms to the Catholic hierarchy.

NEWS BOX

World Bank Announces Record $100 Billion Support For World's Poorest Countries

Washington, United States. The World Bank announced Thursday that it had raised close to $24 billion to provide loans and grants for some of the world's poorest nations, which it can leverage to generate a record $100 billion in total spending power. Donor countries committed $23.7 billion to replenish the bank's concessional lending arm, known as the International Development Association (IDA), a World Bank spokesperson told AFP, marking a slight increase from the roughly $23.5 billion pledged during the last fundraising round three years ago.

The Bank can use this money to borrow on financial markets, allowing it to leverage the amount raised by around four times, unlocking around $100 billion in new loans and grants, up from $93 billion in 2021.

"We believe the historic success of this IDA21 replenishment is a vote of confidence and support from donors and clients," a World Bank statement read, referring to the current IDA funding round.

"This funding will be deployed to support the 78 countries that need it most," World Bank President Ajay Banga said in a separate statement, referring to the developing countries that are eligible for IDA support. It would, he added, help provide "resources to invest in health, education, infrastructure, and climate resilience," as well as helping to stabilize economies and create jobs.The World Bank's announcement follows two days of talks in the South Korean capital, Seoul, a city still reeling after President Yoon Suk Yeol declared martial law late on Tuesday local time, before backtracking under pressure from lawmakers. IDA has become the single largest source of concessional, or below-market, climate finance, and around two-thirds of all IDA funding over the past decade has gone to support countries in Africa, according to the World Bank. IDA replenishment is a crucial part of the Bank's operations, and happens once every three years, with much of the funding coming from the United States, Japan and several European countries including the United Kingdom, Germany and France. This year, the United States announced ahead of time that it would commit a record $4 billion in new funding to the IDA, while other countries -- including Norway and Spain -- also significantly stepped up their financial support.

Thirty-five former recipients of IDA assistance have graduated from developing economy status in recent decades, including China, Turkey and South Korea, with many of them now donors to the fund.

French President Macron Vows To Stay In Office Despite No-confidence Vote, Pledges To Appoint New PM Soon

Paris. French President Emmanuel Macron vowed to continue his five-year mandate despite the recent no-confidence vote that led to the resignation of Prime Minister Michel Barnier. Macron also emphasised his responsibility to ensure the continuity of the state, the proper functioning of institutions, and the protection of the French people. The remarks by the French President came while he addressed the nation on Thursday from the Elysee Palace. "Finally, the mandate that you democratically entrusted to me is a five-year mandate, and I will exercise it fully until its end. My responsibility requires ensuring the continuity of the State, the proper functioning of our institutions, the independence of our country, and the protection of all of you." He added, "I have been doing this from the beginning, at your side, through social crises, the Covid-19 epidemic, the return of war, inflation and so many trials that we have shared," Elysee said. He said, "From today, a new era must begin where everyone must act for France and where new compromises must be built. Because the planet is moving forward, because the challenges are numerous and because we must be ambitious for France. We cannot afford divisions or inaction."

"This is why I will appoint a Prime Minister in the coming days. I will charge him with forming a government of general interest representing all the political forces of an arc of government, who can participate in it or at least who undertake not to censor it. The Prime Minister will have to lead these consultations and form a tight government at your service," Macron said.

Hezbollah Vows Support For Syrian Govt Amid Rebel Offensives

Beirut. Hezbollah will support the Syrian government amid escalating offensives by rebel forces, Hezbollah leader Sheikh Naim Qassem said in a televised speech.

While Qassem did not clarify the form of support, he assured on Thursday that Hezbollah would "do what it could". Qassem accused the US and Israel of instigating aggression against Syria due to their failure in Gaza. He also claimed that "terrorist groups" sought to shift Syria's alignment from supporting the resistance to backing Israeli occupation, Xinhua news agency reported. "We face a very dangerous Israeli project against the Middle East," he warned.

His comments came hours after Syrian opposition forces captured the strategic city of Homs in central Syria, marking a significant advance in their offensive that started on November 27. The rebels had previously seized Aleppo, Syria's second-largest city, in earlier assaults. The United Nations World Food Program reported that more than 280,000 people had been displaced by the recent violence, according to a post on X.

Bangladesh To Remove Sheikh Mujibur Rahman's Image Off Currency Notes

According to the central bank, banknotes of Taka 20, 100, 500, and 1,000 are being printed on the instructions of the interim government.

Dhaka. Months after the ouster of Sheikh Hasina as prime minister, Bangladesh has begun the process of erasing the image of Sheikh Mujibur Rahman -– her father and the iconic figure behind the founding of the country -- from its currency notes.

Bangladesh Bank is printing new notes, including in them features of the July uprising, the Dhaka Tribune reported Thursday, referring to the student-led protests that forced Hasina to flee to India on August 5. Nobel laureate Muhammad Yunus took charge as Chief Adviser, the head of an interim government.

According to the central bank, banknotes of Taka 20, 100, 500, and 1,000 are being printed on the instructions of the interim government."The new notes will not include image of 'Bangabandhu' Sheikh Mujibur Rahman," the paper reported, quoting the bank.Religious structures, Bengali traditions, and "graffiti" drawn during the July uprising will be included, it said."I hope the new note could be released in the market within the next six months," it quoted Bangladesh Bank executive director Husneara Shikha as saying.

According to the paper, officials from the bank and the Ministry of Finance said the leader's image will be removed from the current notes. Initially, the design of the four notes is being changed, and the others will be redesigned in phases, they said.

The Finance Ministry's Finance Institute Division submitted a detailed design proposal for the new notes in September.

The legacy of Mujibur Rahman – often called the Father of the Nation – came under attack during the protests, which were initially against a controversial job quota. His statues and murals bearing his image were targeted as his daughter fled to India, and is reported to be still living there.She has directly targeted Yunus in recent remarks, accusing him of failing to protect the minorities, including Hindus.

Bangladesh's International Crimes Tribunal has termed her remarks as "hate speech", and the country's leaders said a smear campaign is on against the Yunus government.

Police release new photos as they search for gunman who killed UnitedHealthcare CEO

NEW YORK. The masked gunman who stalked and killed the head of one of the largest U.S. health insurers had the words "deny," "defend" and "depose" emblazoned on his ammunition, echoing a phrase used by industry critics, two law enforcement officials said Thursday.

The words were written in permanent marker, according to one of the officials, who were not authorized to publicly discuss details of the investigation into the shooting early Wednesday outside a Manhattan hotel and spoke to The Associated Press on the condition of anonymity.

With the gunman still at large, police also released photos of a "person of interest" wanted for questioning in connection with the killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.The images, showing an unmasked man in the lobby of a Manhattan hostel, add to a collection of photos and video that have circulated since the shooting — including footage of the attack itself, as well as still frames of the suspected gunman stopping at a Starbucks beforehand.Thompson, 50, died in a dawn ambush as he walked from his midtown hotel to the company's annual investor conference at a Hilton across the street, blocks from tourist draws such as Radio City Music Hall, the Museum of Modern Art and Rockefeller Center, where the famed Christmas tree was lit Wednesday night. The reason for the killing remained unknown, but New York

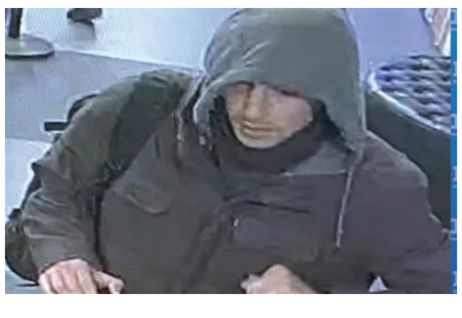

City police say evidence firmly points to it being a targeted attack.

The messages on the ammunition mimic the phrase "delay, deny, defend," which is commonly used by lawyers and insurance industry critics to describe tactics used to avoid paying claims. It refers to insurers delaying payment, denying a claim and then defending their actions. Health insurers like UnitedHealthcare have become frequent targets of criticism from doctors and patients for denying claims or complicating access to care.

Investigators recovered several 9 mm shell casings from outside the Hilton and a cellphone from the alleyway through which the shooter fled. Inside a nearby trash can, they found a water bottle and protein bar wrapper that they say the gunman purchased from Starbucks minutes before the shooting. The city's crime lab is examining those items for DNA and fingerprints.The killing and the shooter's movements in the minutes before and afterward were captured on some of the multitude of security cameras in that part of the city. The shooter fled on a bicycle and was last seen riding into Central Park.

A tip that the shooter may have stayed at a hostel brought police Thursday morning to at least two such establishments on Manhattan's Upper West Side, according to one of the law enforcement officials briefed on the investigation. The photos made public Thursday were taken in the lobby of the HI New York City hostel."We are fully cooperating with the NYPD and, as this is an active investigation, can not comment at this time.

Student's Science Project With Bird Poop Leads To Discovery Of Cancer-Fighting Compound

World. Young school students from the James R Jordan Boys and Girls Club in Chicago made a groundbreaking discovery while studying goose poop in a local park. The school students, under the supervision of researchers from the University of Illinois and Professor Brian Murphy at Chicago, identified a potential cancer-fighting compound. The students participated in a STEM program that turned them into bona fide biomedical scientists before they even started high school. Students carefully isolated a bacterium from the goose poop that showed antibiotic activity. The findings were published in the journal ACS Omega, with student Camarria Williams credited as a co-author.Professor Murphy's research laboratory is focused on discovering antibiotics from natural sources, and the cohort of young scientists participated by supplying environmental samples from their local communities.According to a press release by the American Chemical Society, one of the 14 samples of goose poop collected from the Garfield Park Lagoon contained a strain of bacteria called Pseudomonas idahoensis. The students interpreted the bacterium's bioassay data and concluded it had antibiotic activity

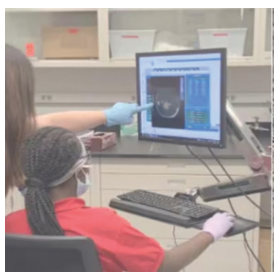

and produced a never-before-seen compound.

Then, the university researchers determined the compound's molecular structure using nuclear magnetic resonance and mass spectrometry, named it orfamide N after the family of molecules it belongs to, and investigated its biological activity.

Although orfamide N was not responsible for the antibiotic activity that the team initially observed from P idahoensis, the compound inhibited the growth of human melanoma and ovarian cancer cells in culture tests. Further studies could reveal other advantageous properties of this newly characterised molecule, as per the ACS release.The researchers say that this work proves that it's possible to combine educational outreach with natural product discovery research, and it emphasises the importance of a strong relationship between universities and their local communities.

These school students' work is an inspiring example of how curiosity and learning can lead to significant breakthroughs, even in unexpected places. Camarria Williams, a student, was listed as a co-author on the findings, which were published in the journal ACS Omega.

EAM Jaishankar Highlights Potential Of India-Japan Semiconductor Collaboration

New Delhi. At the India-Japan Forum's Inaugural Session, External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar highlighted the burgeoning potential for semiconductor collaboration between India and Japan, emphasising its significance in reshaping global geopolitical dynamics.

He pointed out that both nations, while revitalising their semiconductor industries, are also working with Taiwan, paving the way for a transformative partnership in this vital sector. Japan is today revitalising its semiconductor sector, and India, after a very long period of neglect, has announced a semiconductor mission. There are a lot of things happening. It is interesting that both of us also happen to be working with Taiwan.

TRENDING NOWI'm seeing the beginnings of something potentially important here, and potentially really significant for both countries," he said, underlining the strategic importance of the endeavour.

Jaishankar acknowledged the nascent stage of this collaboration but noted its exceptional promise, placing it among the top five areas of focus despite its early phase. "Normally, I would say, 'Okay, it's just beginning... but in this case, I would make an exception, because I think this is such a vital field which is going to be so important in a way that balances geopolitical level equations in this coming decade," he remarked. He also stressed the growing interest and determination among stakeholders from both nations to deepen ties and address past shortcomings in their bilateral relationship. "I hear much more discussion and interest, and initiatives actually from organisations and people who have been involved in the relationship, which is really at one level, some dissatisfaction about why we have not been able to do more, but also some determination that we want to do more," Jaishankar said, adding that industry-level initiatives, such as boosting training and language skills, have been promising steps forward.

George RR Martin Provides Disappointing Update On Future Of 'The Winds Of Winter' Book

For the first time, George RR Martin expressed doubt that he'll ever finish writing the next entry in the series.

WORLD. American author George RR Martin does not know if he will ever finish The Winds of Winter, the next book in the A Song of Ice and Fire fantasy series which birthed the iconic Game of Thrones (GoT) TV series on HBO. Mr Martin released the last book in the series, A Dance with Dragons, 13 years ago when the first episode of GoT aired the same year. While the TV series may have concluded with its rather rushed and disappointing ending, the fans of the books have been waiting for Mr Martin to come up with the instalment to give his take on the ending.However, speaking to Hollywood Reporter, Mr Martin for the first time, expressed doubt that he'll ever finish writing the next entry in the series.Unfortunately, I am 13 years late. Every time I say that, I'm [like], 'How could I be 13 years late?' I don't know, it happens a day at a time," said Mr Martin.

"But that's still a priority. A lot of people are already writing obituaries for me. [They're saying] 'Oh, he'll never be finished.' Maybe they're right. I don't know. I'm alive right now! I seem pretty vital!" he added.Quizzed about retirement, Mr Martin said that he could never retire as he's "not a golfer".Social media users were left disappointed by the update from Mr Martin with some saying they had made peace with the fact that he may never finish the book series.

"As disappointing as this is, at least we don't have to wait anymore. It ain't coming, y'all," said one user, while another added: "George is the kind of guy to keep saying "I've almost finished", when he hasn't even started."A third commented: "He's been talking about Winds of Winter since before the Game of Thrones TV series even came out, so I'm betting it will never get done."This is not the first instance when GRRM has been pressed about the future of the series. A few years ago, Mr Martin said the final books in the series were drifting "further and further away" from the TV show.Another question that I get a lot, especially since the end of Game of Thrones on HBO, is whether A Song of Ice and Fire will end the same way," Mr Martin said. "An architect would be able to give a short, concise, simple answer to that, but I am much more of a gardener. My stories grow and evolve and change as I write them.""I generally know where I am going, sure…the final destinations, the big set pieces, they have been in my head for years…for decades, in the case of A Song of Ice and Fire. There are lots of devils in the details, though, and sometimes the ground changes under my feet as the words pour forth," he added.

NEWS BOX

Big blow to India as shooting, hockey out of 2026 Youth Olympics

NEW DELHI. In a significant setback to India's medal prospects, the International Olympic Committee (IOC) executive board has removed shooting, weightlifting, and hockey from the roster of medal sports for the much-anticipated 2026 Youth Olympic Games (YOG) in Dakar, Senegal. The decision was made during a meeting held in Lausanne on December 3, where the IOC confirmed the events and athlete quotas for the Games, scheduled to take place from October 31 to November 13, 2026.

The IOC announced that all 35 International Federations (IFs) would maintain official involvement in Dakar 2026, with 25 sports included in the competition programme and 10 designated as part of the engagement programme. The engagement programme will showcase non-medal sports, including canoe-kayak, golf, hockey, karate, modern pentathlon, shooting, sport climbing, surfing, tennis, and weightlifting.

Dakar 2026 will feature one discipline from each of the 25 medal sports, which include athletics, aquatics, archery, badminton, baseball, basketball, boxing, breaking, cycling, equestrian, fencing, futsal, gymnastics, handball, judo, coastal rowing, rugby sevens, sailing, skateboarding, table tennis, taekwondo, triathlon, beach volleyball, beach wrestling, and wushu.

This marks a sharp contrast from the 2018 Youth Olympics in Buenos Aires, where India won 13 medals, including three golds, nine silvers, and one bronze. Shooting alone contributed four medals, including two golds and two silvers, while hockey and weightlifting added two silvers and one gold, respectively.The absence of shooting, weightlifting, and hockey from the medal events is likely to impact India's performance significantly. In 2018, star shooter Manu Bhaker secured gold in the girls' 10m air pistol and silver in the mixed 10m air pistol, while Simran Kaur earned a silver in the girl's freestyle 43kg wrestling. However, in Dakar 2026, wrestling will only feature as beach wrestling.The IOC emphasized that the excluded sports would still hold a presence through interactive activities on-site and digital platforms, highlighting their importance as integral components of the Youth Olympic Games.

The Dakar YOG will feature 151 events, a reduction from the 241 events held during the Buenos Aires edition, with an equal distribution of 72 events each for men and women, alongside seven mixed-gender events. The total athlete quota has been set at 2,700.The IOC noted that full gender equality would be achieved for the first time in Summer YOG history, not only in the overall athlete quota but also across every sport, discipline, and event. This decision aligns with the IOC's commitment to delivering a streamlined and efficient programme while maintaining the competition's elite nature.

As National Wrestling Championships begin on December 6, WFI to discuss RSPB's decision to skip event in AGM

The source, however, said this decision has been depriving several wrestlers from competing in the nationals.

CHENNAI. Even as the National Wrestling Championships begins in Bengaluru on Friday, all eyes will be on the annual general meeting (AGM) of the Wrestling Federation of India (WFI) scheduled on the last day (Sunday).

As the Railway Sports Promotion Board (RSPB) has decided not to field its wrestlers, the championship, as reported by this daily, will not see participation from most of the country's elite wrestlers including the Paris Olympics bronze medallist Aman Sehrawat.

A similar situation arose last year when the WFI held the nationals in Pune while the ad-hoc panel, which was then running the day-to-day affairs of the federation, organised it in Jaipur with the RSPB being the hosts. "This is the second time, the RSPB is not sending its wrestlers for the nationals. The reason is said to be the sports ministry's order wherein it suspended the WFI. But if that is the case then the Services Sports Control Board (SSCB) should also not have sent the entries for the Bengaluru event. This issue will be discussed in the AGM," a WFI source told this daily.

Coincidentally, Prem Chand Lochab, secretary of the RSPB, is also secretary-general of the wrestling federation. He had told this daily that the Railway wrestlers were not competing in the nationals as the federation has been suspended by the sports ministry.

The source, however, said this decision has been depriving several wrestlers from competing in the nationals. "As many as 12 RSPB wrestlers took part in the state championships of a few states to qualify for the nationals. They will be representing states like Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. This shows how the wrestlers are

desperate to compete but their employer is not allowing them," added the source.

Former national champion Sandeep Mann, who has switched his weight category, is one of such RSPB employees. He will represent his home state Punjab in the 86kg. "Yes, I have won gold in the state championship and qualified for the nationals. The RSPB has neither prevented us nor asked us to compete in the nationals. As I am on leave, I will compete at the event representing Punjab," Mann told this daily.

Another issue which might be discussed in the AGM is devising a criterion to prevent wrestlers from changing their states frequently in their bid to qualify for events like nationals. "Given the tough competitions in the states like Haryana and Maharashtra, fringe wrestlers from these states compete in other units like Delhi and Chandigarh. It has become quite normal but it hurts the chances of wrestlers from these adopted states. The WFI will try to curb this practice by coming up with a criterion," said the source.Meanwhile, the nationals will begin with competitions in the men's freestyle on Friday followed by bouts in Greco-Roman and two weight categories of women's wrestling the next day. The last day will witness competitions in the remaining eight categories of women's wrestling apart from the AGM.s top wrestlers from the RSPB are missing the championship, the tournament will provide a chance to the upcoming wrestlers to win medals in their respective weight categories and stake their claims for the national camp.

England all out for 280 after sizzling Brook century

WELLINGTON. Harry Brook smashed a century before England were dismissed for 280 on day one of the second Test against New Zealand in Wellington on Friday.

Brook top-scored with 123 after the tourists were put in to bat on a green Basin Reserve pitch and he put on a key partnership with Ollie Pope to rescue an England innings which was teetering at 43-4.Brook was run out on the last ball of the second session after powering England out of trouble to 259-7, before the final three wickets fell quickly after tea.The in-form Brook registered his eighth century in just 23 Tests and his dismissal was a major boost for the home side after he and wicketkeeper Pope (66) counter-punched with a stand of 174 off just 158 balls.The partnership was reminiscent of the first Test in Christchurch when the same pair combined for a rapid 151 to rescue their first innings and set up an eight-wicket win for the tourists.Brook went on to score 171 at Hagley Oval and unfurled another sparkling knock at the Basin Reserve, where he scored 186 when the teams met here last year.

The lanky 25-year-old's power once again couldn't be contained by New Zealand's seam-heavy attack, striking five sixes and 11 fours from his 115 balls faced before his concentration slipped.

He set off for a single to short midwicket but Chris Woakes didn't respond and Brook was caught short when bowler Nathan Smith hit the stumps in his follow-through.

It took Brook just 91 balls to bring up three figures, his second-fastest century, with his most notable shots being two towering sixes over extra cover in the first session.

Will O'Rourke (3-49) finally removed Pope, who mis-timed a pull shot, and the pace bowler struck again to dismiss England captain Ben Stokes for two, caught behind.

Smith (4-86) helped to wrap up the tail to cap an impressive start to just his second Test.Matt Henry (2-43) and Smith claimed two early wickets on top to put the hosts well on top.New Zealand's poor catching was a major weakness in Christchurch but there was no repeat, with three batters falling to sharp chances in the field.The impressive Henry had Ben Duckett caught by a diving Tom Latham at second slip without scoring before bowling fellow-opener Zak Crawley for 17.

Smith had both Jacob Bethell (16) and Joe Root (3) caught behind, with Daryl Mitchell grabbing a flyer with one hand at first slip to remove Root.

Champions Trophy 2025: ICC meeting postponed, to reconvene in few days

CHENNAI. Even as the delay in finalising the hosts and schedule of the 2025 Champions Trophy continues, the ICC Board meeting which was supposed to happen on Thursday got postponed at the last minute. It is expected to reconvene in the coming days to finalise a solution for the ongoing issue between India and Pakistan Cricket Boards.

Ever since the BCCI communicated that India will not travel to Pakistan for the Champions Trophy scheduled to happen in February and March next year, there has been a deadlock between the two neighbouring nations and the global cricketing body. The ICC board met briefly on Friday, but no definite solution was achieved.While the BCCI has proposed a

hybrid model, like the Asia Cup last year, PCB had taken a stand, asking for a long-term solution for the issue. They had proposed a new formula where Pakistan, too, will not travel to India for the ICC events till 2031 and that will require a hybrid model for the same.

PCB chief Mohsin Naqvi, who spoke to a few reporters in Dubai on Saturday, had said: "This situation arises all the time. This one-sided thing that we travel to India and they refuse to come to our country cannot continue. At the moment, we are talking to settle it once for all. I promise, whatever will happen will happen on equal terms. Whatever it is, it would be for the long term not only for the Champions Trophy. Things will be decided for the upcoming tournaments as well."Meanwhile, Jay Shah, who was the BCCI secretary till Saturday, taking charge as ICC Chief, visited the global body headquarters in Dubai on Thursday. He met with the ICC staff and the ICC's Media Rights partners at the annual broadcast workshop which was being hosted in Dubai, UAE. With the global cricketing body under pressure from the official broadcast partners to finalise the schedule and venues for the Champions Trophy for them to go ahead .

How live broadcast of ongoing World Chess Championship was arranged

Organisers have ensured no broadcast delays after putting an elaborate security mechanism in place and adopted a time limit to tackle the issue of mobile phone usage by spectators.

SINGAPORE. In the weeks after Singapore won the right to host the World Championship, they had two main requests. Allowing spectators to carry mobile phones at all times was one. And for the broadcast to have no delays. "This was the most commercially attractive set-up for spectators," Kevin Goh, head of the Local Organising Committee, told this daily.

Both of them could have created specific problems and that's why the LOC and FIDE — the world governing body for chess — discussed it at length. While the world body signed off on the request for 'live' broadcast, the two organisations met halfway regarding mobile phones. "We understood that the mobile phones issue... there were complications we couldn't resolve," Goh, the CEO of the Singapore Chess Federation, said."Hopefully, one day we will have the technology to do it. The best way right now is for spectators to bring in their phones and take pictures and videos for the first 30 minutes before going out and depositing it."

FIDE and the LOC, though, were aligned when it came to ensuring there would be

no broadcast delays. It might seem outrageous to suggest not having live broadcast as normal but this is chess in 2024. One regular anti-cheating measure in place at other tournaments is to have deferred transmission (this measure was also present at the Candidates early this year).The organisers ensured no delays after putting an elaborate security mechanism in place. It's so thorough the devices would detect if the players have as much as a cold.

The processOnce the players go down to the playing hall, they are ushered down the corridor and into the players' lounge. From the lounge till the time they enter the fish tank, multiple devices are employed to scan them.

The first layer is the basic frame you see in airports. That's the first security layer. Interestingly, that's so common at all tournaments Goh didn't even count it as a layer. Then comes the NLJD (non-linear junction device). There is also a thermal scanner as well as a device that picks up magnets. There is a fifth security apparatus the players face after the games are done.

"We all agree this is the best outcome for everyone," Goh said. "It doesn't make sense when you have live spectators sitting around and they are looking at it (the game) but the screens aren't live. This is an outcome everybody wanted. To try and balance everything."

'I Was Not Serious When I Was Young': Nitish Reddy On His Cricketing Journey

NEW DELHI. In his own words, he was not "serious" about cricket in his early days. But everything changed for Nitish Reddy when he saw tears rolling down his father's face owing to their financial struggles. It was a transformative moment for the young all-rounder who vowed to work harder and achieve success in the game, which culminated in a fine debut for India in the first Test against Australia at Perth.Reddy produced an impressive show, scoring 41 and 38 runs in the two innings against the likes of Pat Cummins, Mitchell Starc and Josh Hazlewood at Optus Stadium. He also claimed a wicket as India registered a massive 295-run win."To be honest, I was not serious when I was young," he said in a video released by the BCCI on Thursday."My father left his job for me and there has been a lot of sacrifice behind my story. One day, I saw him crying because of the financial problems we were facing, and I

was like, this is not how you can be... that my father made the sacrifices and you play cricket just for fun."At that time, I became serious and I got the growth. I worked hard and it paid off. As a son from a middle-class family, I am so proud that my father is happy now. I gave my first jersey to him and saw the happiness in his face," he added.The 21-year-old is likely to retain his spot in the Pink-ball second Test at Adelaide Oval, having slammed 42 off 32 balls in the day-night warm-up match against the Prime Minister's XI in Canberra.In the second innings at Perth, Reddy shared an unbroken 77-run partnership with his hero Virat Kohli, who handed him his maiden Test cap ahead, thus fulfilling a childhood dream.

Recalling the time when he took a selfie with Kohli and his actor wife Anushka Sharma during the 2018 BCCI awards night, Reddy said, "This was a safety photo, at the time he (Virat Kohli) was so famous. I felt that if I don't get a chance for photo later, let's take a picture now.

Twilight challenge: Upbeat India take on desperate Australia

Having taken a 1-0 lead, Rohit and Co will look to repeat all the things they did right in Perth

CHENNAI. It's that time of the tour Down Under again. The breathtaking evening skies of Adelaide and Test cricket under the lights with the pink-ball seaming around like nobody's business. The Indian team, and fans, wouldn't forget the last time they were here.36 all out. While fans would never want to relive it again, back then, Ravi Shastri, who was the head coach of the team, had asked the team to wear their lowest Test score ever like a badge of honour. And boy, did they do. From arguably the lowest point of Indian cricket on the field in the last decade, they made it into what is perhaps the greatest Test series win for the country.Four years on, as India are back in South Australia for yet another pink-ball contest, it is hard to say whether they will be looking at the scars of that match or the glory that followed. However, things are clearly different from 2020.For starters, India is coming into the match with a 1-0 lead in Perth. More than the win, the manner in which it happened and the way the younger generation rose to the occasion on their first visit Down Under will give them a lot of confidence. So much so that captain Rohit Sharma, who was injured and missed the last pink-ball Test, had pushed himself down the order to keep the successful KL Rahul-Yashasvi Jaiswal pair at the top. Then there are the likes of Nitish Kumar Reddy and Harshit Rana who showed that they belong at the highest level on debut in Perth.In a very "kids these days" way, Sharma attributed their success to not having the baggage of the past. In fact, it has been the trend every time India visited Australia in the last decade. From Rishabh Pant to Shubman Gill to now Jaiswal, they have all succeeded on their first trip Down Under."When we came to Australia for the first time, we only thought about how to

make runs. We put a lot of pressure on ourselves. But look, every generation is different. The boys of today are very fearless. And I think this is working in their favour. Whenever I talk to them or listen to them, they only think about how to win the match. When you start thinking like this, individual performances happen on their own... I don't know if anyone talks to them about these things. This is their natural mindset," explained Sharma.

That said, the next few days will not be easy. Australia are yet to lose a day-night Test in Adelaide and are desperate for a win. They have brought in Scott Boland but will have to make do with Marnus Labuschagne as their fifth bowler should Mitch Marsh not bowl. Despite that, they will pose a significant threat, especially under lights. It all might come down to who wins the toss and who gets to bat under lights and how they survive that phase.While another loss could put Australia under immense pressure, a win for India would do a world of good. They would have taken a crucial step towards not just winning the series but also having a chance at the WTC final. Sharma, while acknowledging that it is all about adapting and making good decisions on the field, said they want to build on the win in Perth and move forward. "If we keep doing the things that we did in Perth, I think we can get the result that we are looking for," he said.

Alia Bhatt

Wears A Mask, Keeps It Stylish In Comfy Casuals As She Gets Papped In The City

Alia Bhatt is one of the most loved actresses and she has always impressed fans with her fashion sense. Today, she was spotted in the city, effortlessly blending style and comfort in her casual attire. The Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani actress was papped by shutterbugs as she stepped out wearing a mask. The video of her outing has gone viral on social media.In the video, shared by Filmygyan, we can see Alia Bhatt coming out of a jetty ride. She looks cool in pants and a top. She is holding her bottle and also greeted paps. One of the fans wrote, "Pretty." Many have dropped heart emojis in the comment. Recently, she was spotted with Ranbir Kapoor at the airport. Both were twinning in a white colour outfit.

Recently, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor were spotted enjoying an exciting evening at the Indian Super League on Saturday, cheering for Ranbir's team, Mumbai City FC as it played against Hyderabad FC, in Mumbai. Both actors kept their outfits casual yet stylish — Ranbir opted for a Mumbai City FC jersey, while Alia sported a chic black oversized shirt layered over a white tank top. But the real scene-stealer was their little one, baby Raha, who joined in on the fun dressed in her own mini Mumbai City FC jersey paired with denim and white sneakers. Her adorable game-day look captured hearts as she cheered alongside her parents.Alia Bhatt and Vedang Raina's latest release Jigra is all set to release on OTT. The film will be released on Netflix on December 6, 2024. The OTT platform shared the announcement along with the poster. Fans also reacted to the news and expressed their excitement.

Taking to their Instagram handle, Netflix wrote, "Phoolon aur taaron ne kaha hai, ulti ginti shuru karlo Jigra is arriving tomorrow on Netflix." One of the fans wrote, "One of the finest movies of 2024,watched it in theatres two times.. Alia Bhatt and Vasan Bala made a masterpiece, the genre is quite a new in Bollywood, looking forward to see again in Netflix." Another wrote, "hopefully this film gets it rightfully deserved due now.. cause it hurts to see such a well made film not getting the recognition. it's made like a hollywood movie with the heart of Indian story telling."

Jigra is an action-packed prison-break thriller that centres on the relationship between siblings. Alia Bhatt takes on the role of Satya, while Vedang Raina plays her brother, Ankur. The film is directed by Vasan Bala, with a script by Debashish Irengbam and Vasan Bala.Despite the controversies, Jigra has faced a dismal box office performance. This is the worst opening for an Alia film since 2014, leading many to question its viability in theatres. In comparison, her previous solo hits Raazi and Gangubai Kathiawadi garnered significantly higher opening day collections, between Rs 7.5 crore and Rs 10.5 crore.

Taapsee Pannu's

Interaction With Paparazzi Is Trending: 'Meri Image Achchi Mat Karo'

Taapsee Pannu is known for her acting chops and sartorial fashion. She has mesmerised fans with her performances in films such as Thappad, Haseen Dillruba, and Dunki. Well, Taapsee also makes headlines with her witty remarks and hilarious banter with the paparazzi. Yet again, the actress' interaction with the paparazzi caught the internet's attention.In a video making rounds on the internet, Taapsee was seen leaving a building when paparazzi approached her for photos and videos. However, the actress, who was seemingly in a hurry, said, "Ati hui di thi nah photo.(I had posed before the event.)" Then, one of the paps behind the camera said, "Main nhi aya tha nah. (I wasn't there at that time)" To this, she replied, "Abhi late comers ke liye main kuch nhi kar sakti." (I cannot do anything for the latecomers). In the middle of this, a person added, "Uski gari kho gyi. (His car got towed.)" But the actress was still reluctant to pose for the shutterbugs, and replied, "Toh main kya karu bhai? Meri gaari aa rahi hai piche, hat jao, main kehe rahi hu lag jayegi." (What can I do in that case. My car is coming, please move aside, otherwise you may get hurt.)

One of the shutterbugs, determined to get a better glimpse of Taapsee, complimented her saying, "Aap itna achcha bolti hain." (You speak so well). To this, the actress sarcastically replied, "Mai nhi achcha bolti yaar, kaun bola main achchi bolti hu, main bilkul achcha nhi bolti, meri image achchi mat karo, consistent raho." (I do not speak well friend, who said that I speak well, I do not speak well at all, do not improve my image, be consistent).

This is not the first time when Taapsee indulged in a witty conversation with the paps. Earlier, after an awards night in Mumbai, Taapsee interacted with the paps while exiting the venue with a trophy in her hand. When a paparazzo warmly greeted her and asked how she was, the actress replied, "Main bahut sundar hu. Tum bataao? Aaj kal kaise chal raha hai." (I am very beautiful. Tell me? How are you doing these days?) The light-hearted exchange continued with the pap responding, "Aapko miss kar rahe hain. Aap ek dum cutie ho." (I am missing you. You are so cute). On this, Taapsee responded, "Aur 2-3 achi cheezein bolo. But caption kharab hi likhna, meri image achi mat karna, warna meri unique image kharab ho jaayegi." (Say 2-3 good things. But write a bad caption, don't make my image good. Otherwise my unique image will be ruined).On the work front, Taapsee was last seen in the film Khel Khel Mein. Next, reports suggest that she will portray the role of ACP Komal Sharma in an upcoming comedy movie titled Woh Ladki Hai Kahaan.

Salman Khan, Sanjay Dutt And Sachin Tendulkar Pose For A Rare Photo At Devendra Fadnavis' Swearing-In

A viral photo featuring cricket legend Sachin Tendulkar, Bollywood stars Salman Khan and Sanjay Dutt at the swearing-in ceremony of Devendra Fadnavis in Mumbai has captured the nation's attention. It's a rare frame that combines the worlds of sports, cinema, and politics in one moment.In the photo, Salman Khan is seen flanked by cricket legend Sachin Tendulkar on one side and actor Sanjay Dutt on the other. Salman opted for a sharp look, donning a black suit paired with a maroon shirt underneath. Meanwhile, the Master Blaster kept it casual in a powder-blue shirt. Right behind the trio, actors Arjun Kapoor and Vicky Kaushal can also be spotted, adding more star power to the already iconic frame. Check it out here:

Mumbai's iconic Azad Maidan buzzed with activity on Thursday as business tycoons, Bollywood stars, and key political figures gathered for Devendra Fadnavis' swearing-in as Maharashtra Chief Minister. Fadnavis, who famously said "I'll be back" after the BJP lost power in 2019, was sworn in for his third term. In a significant development, Eknath Shinde took on the role of Deputy Chief Minister, while Ajit Pawar also took the oath for the same position.

Prime Minister Narendra Modi, alongside Chief Ministers from BJP-ruled states and Union Ministers, graced the occasion. The guest list included Bollywood icons like Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Ranbir Kapoor, and Ranveer Singh, as well as business leaders like Pranav Adani and Kumarmangalam Birla.In another video that is going viral on the internet, one can see Salman Khan greeting Shah Rukh Khan with a warm hug. Mukesh Ambani and his family were seen at the ceremony in the first row. Ranveer Singh was also spotted greeting Shah Rukh Khan and Sachin Tendulkar.

Keerthy Suresh's Wedding Invite LEAKED; Actress To Marry Boyfriend Antony Thattil On THIS Date

Keerthy Suresh recently hit the headlines after she made her relationship with longtime boyfriend Antony Thattil Instagram official. The two are all set to get married in a few days, and speculations about their upcoming wedding in Goa have been swirling on the Internet. They will tie the knot on December 12, according to a wedding invite that has been leaked on social media.A wedding invite with the first names of Keerthy and Antony has gone viral on social media. The note, written by Keerthy's parents G Suresh Kumar and Menaka Suresh on the invitation card, reads, "It is our great pleasure to infrom you that our daughter is getting married on December 12 in an intimate gathering. We hold your blessings in high regard and sincerely hope you will keep them in your thoughts and prayers. We would be grateful if you could shower your blessings upon them as they begin a new chapter of their lives together. With warm regards and lots of love G Suresh Kumar and Menaka Suresh Kumar." Check out the viral wedding invite below.

It was on November 27 that the actress shared her first picture with boyfriend Antony Thattil on Instagram. She dropped a throwback photo from their Diwali celebrations and wrote, "15 years and counting It has always been.. AntoNY x KErthy (Iykyk)." A few days later, Keerthy was seen visiting the Tirupati temple. In an interaction with the media outside the temple, she confirmed that she is getting married in December, which is why she came for the darshan of Srivaru. She also revealed that she and Antony will tie the knot in Goa.

Keerthy Suresh and Antony Thattil have been dating for 15 years. Antony is a Dubai-based businessman who reportedly owns a chain of resorts in Kochi. He also owns a couple of companies registered in Chennai, Keerthy's hometown.Meanwhile, on the professional front, Keerthy Suresh was last seen in the Tamil political comedy film 'Raghu Thatha', which released in August. She will soon make her Bollywood debut with the upcoming action thriller 'Baby John', alongside Varun Dhawan. Also starring Wamiqa Gabbi and Jackie Shroff, the film is presented by Jio Studios in association with Atlee and Cine1 Studios. Reportedly, Salman Khan will also make a cameo in Baby John. The film will hit theatres on December 25, 2024.